सर्वहारा दृष्टिकोण

डिजिटल संस्करण
इंटरनेट के जरिये वितरण

सोशलिस्ट यूनिटी सेन्टर ऑफ इण्डिया (कम्युनिस्ट) SUCI (C) का मुखपत्र (पाक्षिक)

वर्ष-41 अंक 2 | 22 जनवरी से 5 फरवरी 2026 | मुख्य संपादकः कॉमरेड प्रभास घोष | कुल पृष्ठ : 8 | मूल्य : 4 रुपये | पृष्ठ 1

महान लेनिन जिन्दाबाद

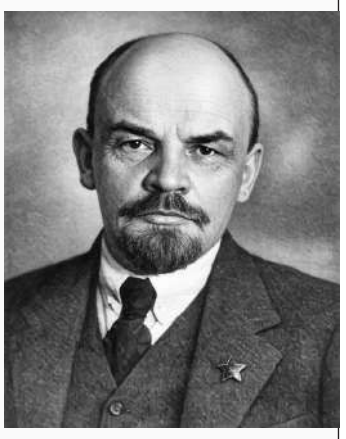

"पार्टी एक वर्ग की अगुआ दस्ता होती है और उसका कर्तव्य जनता का नेतृत्व करना है, न कि केवल जनता के औसत राजनीतिक स्तर को प्रतिबिंबित करना।" (*कृषि के प्रश्न पर, 1917*)

"...असमान विकास– विश्वव्यापी पैमाने पर आधुनिक इजारेदार पूंजीवाद का योगफल है।... ऐसी आर्थिक व्यवस्था के अन्दर, जब तक उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व मौजूद है, साम्राज्यवादी युद्धों का होना एकदम अपरिहार्य है।"(*साम्राज्यवाद, पूंजीवाद की चरम अवस्था*)

"पूंजीवाद से कम्युनिज्म में संक्रमण एक पूरे ऐतिहासिक युग का द्योतक है। जब तक यह युग समाप्त नहीं हो जाता, तब तक अनिवार्य रूप से शोषकों को अपनी बहाली की आशा बंधी रहती है और वह आशा बहाली की कोशिशों में परिवर्तित हो जाती है।" (*सर्वहारा क्रांति और गद्दार काउत्स्की, संग्रहित रचनाएं, खंड-28*)

उन्नाव बलात्कार के आरोपी को जमानत पर रिहा किये जाने पर
एआईएमएसएस ने जतायी चिंता

कुख्यात 2017 उन्नाव बलात्कार मामले में आरोपी कुलदीप सिंह सेंगर की उम्रकैद की सजा को सस्पेंड करने और जमानत देने पर गंभीर चिंता जताते हुए ऑल इण्डिया महिला सांस्कृतिक संगठन (एआईएमएसएस) की महासचिव कॉमरेड छवि मोहंती ने 25 दिसम्बर को जारी एक बयान में कहा कि पीड़िता लड़की के रिश्तेदारों की सुरक्षा को लेकर डर से इनकार नहीं किया जा सकता है।

उन्होंने कहा कि एक जघन्य अपराध के दोषी को ऐसी राहत देना पीड़िता और उसके परिवार के साथ न्याय के खिलाफ है।

उत्तर प्रदेश की भयानक घटना पर बयान

उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक 5 साल की बच्ची से दो युवकों द्वारा दुष्कर्म करने और उसे तीन मंजिली बिल्डिंग से फेंकने की वीभत्स घटना पर एआईएमएसएस की अखिल भारतीय कमेटी की महासचिव कॉमरेड छवि मोहंती ने 5 जनवरी को जारी प्रेस बयान में गहरा दुख जताया।

शव परीक्षण रिपोर्ट में कहा गया है कि बच्ची के साथ यौन हमला किया गया है, उसके शरीर पर कई चोटें आयी हैं और उसका गला घोंटा गया है। पुलिस रिपोर्ट के अनुसार, दोषियों ने कबूल किया है कि उन्होंने उसे मजे के लिए उठाया था।

एआईएमएसएस ने सभी प्रचार माध्यमों के जरिये फैलायी जा रही अश्लीलता, शराब और ड्रग्स की लत से युवाओं पर पड़ने वाले बुरे असर पर गहरी चिंता जतायी, जो हमारे देश में लड़कियों और महिलाओं पर बढ़ते अपराधों का एक बड़ा कारण है।

महिला संगठन ने सरकार से इन बुराइयों को खत्म करने के लिए कड़े कदम उठाने की मांग की। साथ ही यह भी मांग की कि पोस्को के तहत जो अपराधी अभी सलाखों के पीछे हैं, उन्हें कड़ी सजा दी जाए। साथ ही शराब, नशीले पदार्थों की बिक्री और सोशल मीडिया पर अश्लीलता और पोर्नोग्राफी फैलाने पर भी रोक लगाने की मांग की गई। उन्होंने सभी सही सोच वाले लोगों, खासकर मेरठ की महिलाओं से अपील की कि वे सतर्क रहें ताकि अपराधी बच न पायें।

10 केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों और स्वतंत्र सेक्टोरल फेडरेशनों व एसोसिएशनों के संयुक्त मंच के आह्वान पर
12 फरवरी 2026 को राष्ट्रव्यापी आम हड़ताल सफल करें

नई दिल्ली : 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों, सेक्टरों की स्वतंत्र फेडरेशनों और एसोसिएशनों के संयुक्त मंच के तत्वावधान में आंदोलन के अगले चरण पर विचार-विमर्श करने के लिए 9 जनवरी को सुरजीत भवन, दिल्ली में कन्वेंशन आयोजित किया गया, जिसे केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के नेताओं ने संबोधित किया। विभिन्न फेडरेशनों/एसोसिएशनों के नेता भी मौजूद थे। उन्होंने आम हड़ताल समेत आंदोलन के योजनाबद्ध कार्यक्रम में हिस्सा लेने की सहमति दी।

वक्ताओं ने इस बात पर जोर दिया कि कन्वेंशन बहुत ही नाजुक हालात में हो रहा है, जब यूनियन सरकार ने ट्रेड यूनियनों को रोकने और कमजोर करने और पूंजी के हमले के सामने भारत के मजदूर आन्दोलन को बेबस करने के लिए चार लेबर कोड और नियम अधिसूचित किये हैं। उन्होंने कहा कि जब से लेबर कोड लाये गए और संसद में जबरदस्ती पास किये गए, तब से भारत के मजदूरों ने 5 बड़ी आम हड़तालें की हैं। अधिसूचित लेबर कोड और ड्राफ्ट नियम हड़ताल का अधिकार छीनने और सामूहिक सौदेबाजी से वंचित करने के लिए हैं। लगभग 70 प्रतिशत फैक्ट्रियां लेबर कानून के दायरे, नियमन और मालिकों की जिम्मेदारियों से बाहर हो जाएंगी, जिससे श्रमिकों को मालिकों के रहमोकरम पर छोड़ दिया जाएगा। ज्यादातर श्रमिकों को पेशागत सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा से भी बाहर कर दिया जाएगा, सुलह/न्याय निर्णय प्रक्रिया के जरिये मौजूदा अधिकारों और वेतन का बचाव लगभग खत्म कर दिया जाएगा। वेतन की परिभाषा में ही बदलाव का प्रस्ताव है, ट्रेड यूनियन एक्ट को बदलने का प्रस्ताव है ताकि यूनियन बनाना मुश्किल/असंभव हो जाए, जिससे मनमाने ढंग से रजिस्ट्रेशन और मान्यता रद्द हो जाए, सामूहिक ट्रेड यूनियन गतिविधियों के खिलाफ बदले की कार्रवाई हो और मालिकों को अपनी मनमानी करने के लिए अपनी कानूनी

(शेष पृष्ठ 2 पर)

परमाणु ऊर्जा विधेयक से लोगों की जान खतरे में पड़ जाएगी

केंद्र की भाजपा सरकार ने संसद के शरद कालीन सत्र (17-18 दिसंबर) में लोकसभा व राज्यसभा में सभी विपक्षी पार्टियों की बातों को नजरअंदाज करते हुए 'भारत में बदलाव के लिए परमाणु ऊर्जा का सस्टेनेबल इस्तेमाल और एडवांसमेंट' या संक्षेप में 'शांति' विधेयक-2025 पास कर दिया। इतने जरूरी मुद्दे को संसदीय स्थायी समिति को समीक्षा के लिए भेजे बिना और लगभग बिना किसी चर्चा के जबरदस्ती पारित कर दिया गया। फिर, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 20 दिसंबर को बड़े जोश के साथ इस पर हस्ताक्षर करके इसे कानून बना दिया।

केंद्र का तर्क है कि उनके सपनों के 'विकसित भारत' में बिजली की मांग इतनी बढ़ जाएगी कि 2047 तक 100 गीगा वाट परमाणु ऊर्जा बनानी होगी। इसमें से 2031-32 तक 22 गीगा वाट परमाणु ऊर्जा बनाने का लक्ष्य पूरा करना जरूरी है। इसी मकसद से, मौजूदा परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 और परमाणु क्षति के लिए नागरिक दायित्व अधिनियम, 2010 (सीएलएनडी) को रद्द करके 'शांति कानून-2025' लाया गया।

फिर, भारतीय इजारेदार कंपनियां अमेरिका और दूसरे देशों की बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ मिलकर परमाणु ऊर्जा प्लांट लगाएंगी और बिजली बेचकर ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाएंगी। यह कुछ समय से चल रहा है। अमेरिकी ऊर्जा विभाग ने मार्च 2025 में अपने देश की बहुराष्ट्रीय कंपनी 'होलटेक इंटरनेशनल' को निर्यात लाइसेंस दिया ताकि वह भारतीय कंपनियों को एसएमआर-300 तकनीक की आपूर्ति कर सके। इसके बाद, दोनों पक्षों ने भारत-अमेरिका सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट (123 एग्रीमेंट) को लागू करने की पहल की। असल में केंद्र सरकार कई अमेरिकी कंपनियों (होलटेक इंटरनेशनल, डब्ल्यू सी, जीई, हिताची वगैरह) और टाटा, एल एंड टी, अडानी और अंबानी ग्रुप की कंपनियों जैसी भारतीय कंपनियों

(शेष पृष्ठ 2 पर)

जंगखोर अमेरिका द्वारा वेनेजुएला पर किये गए कायराना सैन्य हमले का विरोध

जंगखोर अमेरिकी साम्राज्यवादियों द्वारा वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो व उनकी पत्नी को अमेरिका द्वारा बंधक बनाये जाने और वेनेजुएला पर सैन्य हमला किये जाने के खिलाफ एसयूसीआई (कम्युनिस्ट) के आह्वान पर देशभर में विरोध प्रदर्शन किये गये और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के पुतले दहन किये गये। अब तक प्राप्त खबरों को दिया जा रहा है।

(शेष पृष्ठ 4 पर)

धर्मतल्ला, कोलकाता

जंतर मंतर, दिल्ली

परमाणु ऊर्जा ...

(पृष्ठ 1 का शेष)

के फायदे के लिए यह कानून जल्दबाजी में लायी है।

विदेशी कंपनियों को परमाणु बम का ईंधन देने की पहल

इस नए कानून में ऐसा क्या है जो ऊपर बताए गए दो कानूनों से अलग है? पहला, 1962 के एटॉमिक एनर्जी एक्ट में कहा गया था कि परमाणु ऊर्जा उत्पादन पूरी तरह से सरकारी नियंत्रण में होगा। क्योंकि परमाणु ऊर्जा उत्पादन की प्रक्रिया बहुत मुश्किल और जोखिम भरी है और इसका शुरुआती वित्तीय निवेश बहुत महंगा होता है। मोदी सरकार ने यह कहते हुए इसके उलट तर्क दिया है कि केंद्रीय बजट में आर्थिक संकट के कारण केंद्र सरकार इतना खर्च नहीं कर सकती (हालांकि पूंजीपतियों को लाखों-करोड़ों की सब्सिडी देने के लिए कोई आर्थिक संकट नहीं है)। इसलिए, इस कानून ने पिछली सरकार की रोक हटा दी है और कहा है कि देशी-विदेशी निजी बहुराष्ट्रीय कंपनियां ऐसे परमाणु ऊर्जा प्लांट लगा सकेंगी।

दूसरे, इस कानून में बिजली उत्पादन से होने वाला सारा मुनाफा पूंजीनिवेशकों को जाएगा। लेकिन सारा जोखिम और मुआवजा सरकार यानी असल में जनता की जिम्मेदारी होगी। ये सभी देशी-विदेशी पूंजीनिवेशक परमाणु मिनरलों से भरपूर खदानों से परमाणु ईंधन इकट्ठा करने, न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने, परमाणु ऊर्जा प्लांट चलाने और सबसे ज्यादा कीमत पर बिजली बेचने और आखिर में परमाणु ऊर्जा प्लांट को बंद करने के लिए जिम्मेदार होंगे। और परमाणु ईंधन का उत्पादन, हेवी वॉटर का उत्पादन और रेडियोएक्टिव वेस्ट का प्रबंधन करना सरकार की जिम्मेदारी है, जो बहुत जोखिम भरी, पेचीदी, मुश्किल और महंगी प्रक्रिया हैं। सवाल यह है कि परमाणु ऊर्जा के लिए ईंधन के तौर पर इस्तेमाल होने वाला यूरेनियम-235, जिसका इस्तेमाल परमाणु बम बनाने में हो सकता है, इन देशी-विदेशी गैर-सरकारी बहुराष्ट्रीय संगठनों और निजी कंपनियों के हाथों में कितना सुरक्षित है? नतीजतन, आज देश और जनता की सुरक्षा पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं।

विदेशी कंपनियों के फायदे के लिए रद्द किया गया सीएलएनडी एक्ट 2010

सीएलएनडी एक्ट की धारा 17(ख) में यह साफ किया गया था कि परमाणु हादसा होने पर परमाणु ऊर्जा प्लांट के आपूर्तिकर्ता और रिएक्टर के मालिक की जिम्मेदारी बहुत साफ थी, जिसमें कहा गया था कि ये कंपनियां अपनी मशीनरी व साजो-सामान और कर्मचारियों की खराबी के लिए जिम्मेदार होंगी। अमेरिकी और फ्रांसीसी कंपनियां, भारतीय मालिकों के साथ मिलकर अपनी जिम्मेदारी लोगों पर डालने की कोशिश कर रही हैं। उन्हें खुश करने के लिए 'शांति' कानून में इस धारा को पूरी तरह से हटा दिया गया है।

दूसरी बात, पिछले सीएलएनडी कानून की धारा 46 ने परमाणु हादसा होने पर डायरेक्टरों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की सारी शक्तियां परमाणु ऊर्जा रेगुलेटरों को दी थी। नए 'शांति' एक्ट-2025 में परमाणु हादसा के मामले में डायरेक्टरों या आपूर्तिकर्ताओं को उनकी गलतियों या लापरवाही के लिए सजा देने का कोई प्रावधान या अधिकार सरकार के पास नहीं है।

2008 में केंद्र में कांग्रेस सरकार के राज में भारत-अमेरिकी परमाणु संधि हुई थी, जिससे अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए इस देश में परमाणु ऊर्जा प्लांट में पूंजीनिवेश करने का रास्ता खुल गया था। इसके बावजूद, उस समय की केंद्र की कांग्रेस सरकार को जनमत के दबाव में सीएलएनडी एक्ट 2010 लाना पड़ा था। लेकिन मौजूदा भाजपा सरकार ने पिछले एक दशक से (खासकर ट्रंप के दूसरी बार सत्ता में आने के बाद) अमेरिकी और फ्रांसिसी परमाणु ऊर्जा कंपनियों के दबाव में आकर और उन्हें इस देश में पावर प्लांट लगाने के लिए आकर्षित करने के लिए ऊपर वर्णित दोनों कानूनों को खत्म करके जबरदस्ती यह 'शांति' कानून-2025 लाया है, जिसके जरिये उसने इस देश की इजारेदार पूंजी (अडानी, अंबानी, टाटा वगैरह) को भी परमाणु ऊर्जा प्लांट में पूंजीनिवेश करने की इजाजत दे दी है। नतीजतन, सरकार ने परमाणु ऊर्जा प्लांट हादसों के मामले में जो भी सुरक्षा उपाय और सजाएं थीं, उन्हें भी हटा दिया है।

फिर से ताजा हो गई भोपाल गैस त्रासदी की यादें

3 दिसंबर, 1984 को मध्य प्रदेश के भोपाल में एक भयानक गैस त्रासदी हुई थी। यूनियन कार्बाइड की चलाई जा रही इस फैक्ट्री में जहरीली माइका गैस के असर से हजारों लोग मारे गए थे। आज भी, 40 साल बाद, इसका असर और नतीजे अगली पीढ़ी पर महसूस किए जा रहे हैं। न्यूक्लियर रेडिएशन के असर और नुकसान कहीं ज्यादा भयानक हैं, जिसके नतीजे 80 साल बाद भी जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में महसूस किए जा रहे हैं। हम पहले के सोवियत यूनियन में चेर्नोबिल (1986), जापान में फुकुशिमा (2011) और अमेरिका में थ्री माइल आइलैंड (1979) में न्यूक्लियर पावर प्लांट के भयानक हादसों के बारे में जानते हैं। 40 साल बाद भी, चेर्नोबिल न्यूक्लियर हादसे के असर से 13 यूरोपियन देशों में 161,000 वर्ग मील से ज्यादा इलाके में गंभीर रेडियोएक्टिव नुकसान हुआ है। ऐसे में, 'शांति' कानून-2025 में पर्सनल फिजिकल और प्रॉपर्टी डैमेज से जुड़ी शिकायतों के लिए ज्यादा से ज्यादा समय बीस साल तय किया गया है। जिन लोगों पर विकिरण (रेडिएशन) का असर होगा, उनमें से कई के मामले में इसका बाहरी असर 30-40 साल बाद तक नहीं दिख सकता (खासकर अपाहिज बच्चों के पैदा होने के मामले में)। इसलिए क्योंकि इस एक्ट में 20 साल का समय लिमिटेड है, इसलिए रेडिएशन के असर से प्रभावित ज्यादातर लोगों को कोई मुआवजा नहीं मिलेगा।

इस कानून से शांति नहीं, बल्कि युद्ध का बढ़ेगा खतरा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में कहा, 'परमाणु ऊर्जा एक स्वच्छ ऊर्जा है'। इसीलिए इसका नाम 'शांति' कानून रखा गया है। क्या यह सच है? क्या परमाणु ऊर्जा सच में शांति लाएगी?

पिछला अनुभव कहता है कि इसमें बहुत ज्यादा एक्सीडेंट होने का खतरा रहता है। दूसरा, इससे जो एनरिच्ड यूरेनियम बनेगा, उसका इस्तेमाल न्यूक्लियर हथियार बनाने में किया जा सकता है। भारत एक न्यूक्लियर पावर वाला देश है। उसके पास न्यूक्लियर हथियारों का भंडार है। यह न्यूक्लियर पावर उसे और न्यूक्लियर हथियारों से लैस करेगी, उसे एक बड़ा परमाणु ऊर्जा वाला देश बना देगी, जिससे भविष्य में परमाणु युद्ध की संभावना बढ़ जाएगी। इससे दुनियाभर में अशांति का माहौल बनेगा। हिरोशिमा से नागासाकी तक, चेर्नोबिल से फुकुशिमा और थ्री माइल आइलैंड तक के हादसों ने यह साबित कर दिया है कि परमाणु ऊर्जा बिल्कुल भी स्वच्छ या सेफ नहीं है।

मकसद है परमाणु ऊर्जा तकनीक के लिए बाजार बनाकर मुनाफा कमाना

बहुत से लोग सोचते हैं कि थर्मल पावर प्लांट से प्रदूषण फैलता है। ऐसे में, न्यूक्लियर पावर प्लांट प्रदूषण-मुक्त होते हैं। क्या यह बात पूरी तरह सच है?

जैसा कि इस लेख में पहले बताया गया है, न्यूक्लियर ईंधन और न्यूक्लियर कूड़ा-कबाड़ दोनों से बहुत ज्यादा रेडियोएक्टिव प्रदूषण होता है, जिसका असर कई सालों तक रहता है और पीढ़ी दर पीढ़ी लोग इसके शिकार होते हैं। कैंसर, डिसेबिलिटी, इनफर्टिलिटी इनमें से हैं। इसके लिए जर्मनी समेत कई यूरोपियन देशों ने परमाणु ऊर्जा प्लांट बंद कर दिए हैं। अमेरिका और फ्रांस इन देशों में न्यूक्लियर रिएक्टर लगाने की फिराक में हैं। क्योंकि जन दबाव की वजह से उनके देशों में नए परमाणु ऊर्जा प्लांट नहीं लग रहे हैं। दूसरी तरफ, वे अपनी परमाणु ऊर्जा प्लांट तकनीक के लिए बाजार चाहते हैं। इसलिए वे इसे भारत जैसे देशों को बेचने की फिराक में हैं।

फुकुशिमा में हुए हादसे से सीख लेकर जापान नए परमाणु ऊर्जा प्लांट नहीं लगा रहा है। दुनिया भर के पर्यावरणविद परमाणु ऊर्जा प्लांट की रेडियोएक्टिविटी के खिलाफ बोल रहे हैं। वे प्रदूषण-मुक्त वैकल्पिक ऊर्जा की मांग कर रहे हैं। इस देश में प्रदूषण-मुक्त वैकल्पिक ऊर्जा की संभावना भी बहुत ज्यादा है। खासकर सोलर पावर, हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर और पवन ऊर्जा। लेकिन भाजपा सरकार देशी-विदेशी इजारेदारों और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के फायदे के लिए न्यूक्लियर रिएक्टर लगाकर इस देश के लोगों को एक नई भयानक तबाही की ओर धकेल रही है।

उम्मीद है, देश के लोग इसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। ऑल इंडिया कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉइज एंड इंजीनियर्स (NCCOEE) ने इसके खिलाफ आवाज उठायी है। केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों के संयुक्त मंच और किसानों और खेती-किसानी से जुड़े लोगों के साझे मंच 'संयुक्त किसान मोर्चा' ने इसके खिलाफ आंदोलन गठित करने का आह्वान किया है। देश के सभी जानकार लोग इसके खतरे को समझते हुए इसके खिलाफ जरूर आवाज उठाएंगे।

12 फरवरी की आम हड़ताल...

(पृष्ठ 1 का शेष)

जिम्मेदारियों का उल्लंघन करने का लाइसेंस मिल जाए। कुल मिलाकर, लेबर कोड सरकार द्वारा साफ तौर पर इस तरह से डिजाइन किये गए हैं कि मजदूर-कर्मचारियों और उनकी ट्रेड यूनियनों पर गुलामी की हालत थोपी जा सके ताकि उनके कॉर्पोरेट मालिकों को मजदूर-किसानों व आम लोगों पर अपनी लूट जारी रखने में आसानी हो।

यह डावांडोल अर्थव्यवस्था, बढ़ती बेरोजगारी, लोगों के जनवादी अधिकारों पर बढ़ते हमले, अल्पसंख्यकों के खिलाफ ध्रुवीकरण और नफरत की जहरीली मुहिम, सभी जनवादी संस्थानों पर हमले और उन्हें सत्ताधारी पार्टी के अंधभक्तों से भरने जैसी चिंताजनक स्थिति की पृष्ठभूमि में हुआ है, जिनका एजेंडा सभा, अभिव्यक्ति और असहमति की आजादी को खत्म करना है।

सरकार रेलवे, बंदरगाह, कोयला खदानों, तेल, स्टील, रक्षा, रोडवेज, एयरपोर्ट्स, बैंक, बीमा, टेलीकॉम, डाक, परमाणु ऊर्जा, बिजली उत्पादन और वितरण वगैरह जैसी सभी रणनीतिक महत्व के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों और जन सेवाओं को निजीकरण कर इन्हें बेचने का अपना एजेंडा जारी रखे हुए है ताकि देशी-विदेशी बड़े कॉर्पोरेटों को फायदा हो सके, जिससे देशी औद्योगिक विकास और आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था खतरे में पड़ रही है। बेरोजगारी खतरनाक रूप से बढ़ रही है और सरकार 65 लाख खाली पोस्ट नहीं भर रही है, बल्कि सेवानिवृत्त लोगों को अनुबंध श्रमिक के तौर पर नौकरी पर रखा जा रहा है। जब से आंदोलनकारी किसानों ने सरकार को तीन कृषि कानून वापस लेने पर मजबूर किया है, तब से सरकार अलग-अलग तरीकों से किसानों के खिलाफ नीतियां अपना रही है। ये कानून खेती को कॉर्पोरेट बनाने और कुछ चुने हुए कॉर्पोरेट घरानों के फायदे के लिए जमीन हड़पने के लिए लाये गए थे। अभी भी कृषि क्षेत्र संकट में है, जिससे लोग शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं।

शिक्षा और स्वास्थ्य का व्यापारीकरण लोगों के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि वे इसका खर्च नहीं उठा सकते। जरूरी चीजों की कीमतें बेरोकटोक बढ़ रही हैं। असमानता बढ़ने से बहुत बड़ी संख्या में लोग गरीबी रेखा से नीचे की जिंदगी जीने को मजबूर हो रहे हैं।

केंद्र सरकार लोगों की जायज मांगों को सुनने और मानने के बजाय, कॉर्पोरेट जगत में अपने चहेतों के फायदे के लिए सभी वर्गों पर हमला कर रही है। बल्कि सरकार रोजगार का बड़ा हिस्सा देने वाले छोटे व्यापार-वाणिज्य और मझोले उद्योगों के नुकसान के लिए विदेशी कंपनियों को छूट और फायदा देने में व्यस्त है। ट्रंप के टैरिफ बढ़ाने के एलान के बाद, सरकार विदेशी व्यापार में भारत का हिस्सा छोड़ रही है।

सरकार एक बार फिर हितधारकों से बात किये बिना ड्राफ्ट लेबर पॉलिसी-श्रम शक्ति नीति-2025 लेकर आयी है। यह नीति चार लेबर कोड को लागू करने पर जोर देने के लिए लायी गई है। इसकी साफ दिशा ट्रेड यूनियनों की भूमिका को खत्म करना है। काम/मजदूरी को धर्म कहा गया है, अधिकार नहीं। सरकार की भूमिका को नियामक और कानूनों के पालन/लागू करने वाले से बदलकर तथाकथित रोजगार को आसान बनाने वाले की एक अस्पष्ट, गुमराह करने वाली भूमिका में लाना है। इसके अलावा, सरकार का काम सामूहिक सौदेबाजी को कमजोर करना, मजदूर जगत में समीक्षा के लिए प्रस्तावित नेशनल बॉडी के साथ त्रिपक्षीय वार्ता को छोड़ना, केंद्र में सत्ता के संकेंद्रण के लिए राज्य सरकारों की भूमिका को हड़पना और निरीक्षण और कार्यान्वयन से छुटकारा पाना आदि है।

कन्वेंशन ने ये मांग की:

- चार लेबर कोड और नियमों को खत्म किया जाए।
- "सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया (SHANTI) एक्ट" को वापस लिया जाए, जो निजी और देशी-विदेशी कारोबारियों को मुनाफा पहुंचाने के मकसद से बहुत ज्यादा जोखिमभरे और खतरनाक परमाणु ऊर्जा उत्पादन में आने देगा;
- मनरेगा को फिर से शुरू करें और विकसित भारत-रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) कानून 2025 को निरस्त करें।
- बीमा कंपनियों में 100% एफडीआई का फैसला वापस लें।
- विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान बिल-2025 वापस लें।
- ड्राफ्ट बीज बिल और ड्राफ्ट बिजली (संशोधन) बिल वापस लें।

कन्वेंशन ने इन मुद्दों पर जमीनी स्तर पर बड़ा अभियान चलाने का फैसला किया, जिसकी परिणति 12 फरवरी को एक बड़ी राष्ट्रव्यापी आम हड़ताल में होगी। संयुक्त किसान मोर्चा और खेती-बाड़ी करने वालों के संयुक्त मंच ने भी अपना पूरा समर्थन देने का फैसला किया है।

कन्वेंशन ने फैसला किया कि अगर सरकार अभी भी इन कोड के तहत नियमों को लागू करने की कोशिश करती है और ये कोड रद्द नहीं करती है, तो केंद्रीय ट्रेड यूनियनें अनिश्चितकालीन आम हड़ताल के अलावा, सेक्टरवार विरोध प्रदर्शन के कार्यक्रम के लिए और कड़े कदम उठाने पर मजबूर होंगी। कन्वेंशन ने बीज बिल 2025, ड्राफ्ट बिजली (संशोधन) बिल 2025, वीबी-जीरामजी एक्ट, 2025 के खिलाफ और दूसरी मांगों के समर्थन में गांवों और ब्लॉक स्तर पर 16 जनवरी 2026 को प्रतिरोध दिवस मनाने के संयुक्त किसान मोर्चे के आह्वान को केंद्रीय ट्रेड यूनियनों का समर्थन दिया। केंद्रीय ट्रेड यूनियन इस कार्रवाई में जोरशोर से हिस्सा लेंगी।

केंद्रीय ट्रेड यूनियनें पूरे मजदूर वर्ग और मेहनतकशों के दूसरे तबकों से आगामी आम हड़ताल के लिए कमर कसने, बड़े पैमाने पर अभियान शुरू करने और अपने संगठन को एक जोरदार संघर्ष के लिए तैयार करने का आह्वान करती हैं।

कन्वेंशन ने उनसे और लोगों के दूसरे तबकों, खासकर छात्र-नौजवानों से इस हड़ताल के समर्थन और एकजुटता के लिए आगे आने का आह्वान किया ताकि मेहनतकशों के मौलिक अधिकारों और देश के जनवादी-धर्मनिरपेक्ष ताने-बाने को बचाया जा सके।

पूंजीवादी तथा सर्वहारा-वर्गीय जनवाद

व्लादिमीर लेनिन

सर्वहारा क्रांति और गद्दार काउत्स्की

जिस सवाल को काउत्स्की ने इतने बेहूदा ढंग से उलझा दिया है, वह वास्तव में इस प्रकार है:

यदि हम सामान्य बुद्धि और इतिहास को मुंह नहीं चिढ़ाना चाहते, तो यह स्पष्ट है कि जब तक विभिन्न वर्गों का अस्तित्व है, तब तक हम "शुद्ध जनवाद" की बात नहीं कर सकते, हम केवल वर्गगत जनवाद की बात कर सकते हैं। (प्रसंगवश यह भी बता दिया जाये कि "शुद्ध जनवाद" न केवल एक जाहिलाना फिकरा है, जिससे वर्ग-संघर्ष और राजसत्ता के स्वरूप के बारे में कोई समझ न होने का पता चलता है, बल्कि वह एक हद से ज्यादा खोखला फिकरा भी है, क्योंकि कम्युनिस्ट समाज में परिवर्तित होने और एक आदत बन जाने के दौरान जनवाद का धीरे-धीरे लोप हो जायेगा, लेकिन वह "शुद्ध" जनवाद कभी नहीं बनेगा।)

"शुद्ध जनवाद" एक ऐसे उदारतावादी का झूठ से भरा हुआ फिकरा है, जो मजदूरों को बेवकूफ बनाना चाहता है। इतिहास उस पूंजीवादी जनवाद से परिचित है, जो सामंतवाद का स्थान ले लेता है और उस सर्वहारा जनवाद से परिचित है, जो पूंजीवादी जनवाद का स्थान ले लेता है।

जब काउत्स्की इस सत्य को सिद्ध करने में दर्जनों पन्ने रंग देते हैं कि मध्ययुगीनता की तुलना में पूंजीवादी जनवाद प्रगतिशील है और यह कि सर्वहारा वर्ग को पूंजीपति वर्ग के खिलाफ अपने संघर्ष में निश्चित रूप से उसका लाभ उठाना चाहिए, तो यह मजदूरों को बेवकूफ बनाने के उद्देश्य से की जानेवाली उदारतावादी बकवास है। यह न केवल सुशिक्षित जर्मनी के लिए, बल्कि अशिक्षित रूस के लिए भी एक स्वयंसिद्ध सत्य है। जब काउत्स्की आधुनिक, अर्थात पूंजीवादी, जनवाद के पूंजीवादी सारतत्व के बारे में बताने से बचने के लिए बड़े रोब के साथ वीटलिंग तथा पारागुआ के जेसुइट मतावलम्बियों तथा बहुत-सी अन्य बातों का उल्लेख करते हैं, तब वे मजदूरों की आंखों में केवल "विद्वत्तापूर्वक" धूल झोंकते हैं।

काउत्स्की मार्क्सवाद की हर वह चीज ग्रहण कर लेते हैं, जो उदारतावादियों को, पूंजीपति वर्ग को स्वीकार्य है (मध्य युग की आलोचना, आम तौर से पूरे पूंजीवाद की और खास तौर से पूंजीवादी जनवाद की प्रगतिशील ऐतिहासिक भूमिका) और हर उस चीज को ठुकरा देते हैं, चुपचाप टाल जाते हैं या देखकर अनदेखा कर देते हैं, जो पूंजीपति वर्ग को स्वीकार्य नहीं है (पूंजीपति वर्ग को नष्ट कर देने के लिए उसके खिलाफ सर्वहारा वर्ग की क्रांतिकारी हिंसा)। यही कारण है कि काउत्स्की, अपनी वस्तुपरक स्थिति के कारण और अपने आत्मपरक विश्वास से निरपेक्ष, अनिवार्य रूप से पूंजीपति वर्ग के टुकड़खोर साबित होते हैं।

यद्यपि पूंजीवादी जनवाद मध्ययुगीनता की तुलना में आगे की दिशा में एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम है, पर वह हमेशा सीमित, क्षत-विक्षत, झूठ और मक्कारी से भरा हुआ होता है। वह धनवानों के लिए एक स्वर्ग और शोषितों के लिए, गरीबों के लिए एक जाल और एक धोखा होता है। पूंजीवादी व्यवस्था में वह इसके अतिरिक्त और कुछ हो ही नहीं सकता। यही वह सत्य है, जो मार्क्स की शिक्षाओं का एक सबसे आवश्यक अंग है, जिसे "मार्क्सवादी" काउत्स्की नहीं समझ पाये। इस बुनियादी समस्या पर काउत्स्की उन परिस्थितियों की वैज्ञानिक आलोचना करने के बजाय, जिनके कारण हर पूंजीवादी जनवाद केवल धनवानों का जनवाद बनकर रह जाता है, पूंजीपति वर्ग को "खुश होने की सामग्री" प्रदान करते हैं।

आइये, हम सबसे पहले महापंडित श्री काउत्स्की को मार्क्स तथा एंगेल्स की उन सैद्धांतिक प्रस्थापनाओं की याद दिलायें, जिन्हें (पूंजीपति वर्ग को खुश करने के लिए) ये मूल पाठवादी इतने लज्जाजनक ढंग से "भूल गये हैं" और तब बात को यथासंभव सरल-सुबोध ढंग से समझायें ।

केवल प्राचीन और सामंती राजसत्ता ही नहीं, बल्कि "आधुनिक प्रतिनिधिमूलक राजसत्ता" भी "पूंजी द्वारा उजरती मजदूरों के शोषण का साधन होती है" (अपनी राजसत्ता सम्बन्धी कृति में एंगेल्स)। "चूंकि राजसत्ता केवल एक ऐसी संक्रमणकालीन संस्था है, जिसे संघर्ष में, क्रांति में, अपने शत्रु को बलपूर्वक दबाये रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए स्वतंत्र लोक-राजसत्ता की बात करना निरी बकवास है, क्योंकि जब तक सर्वहारा वर्ग को राजसत्ता की जरूरत है, वह उसे स्वतंत्रता के हित में नहीं, बल्कि अपने शत्रुओं को दबाये रखने के लिए इस्तेमाल करता है और ज्यों ही स्वतंत्रता की बात करना संभव हो जाता है, त्यों ही राजसत्ता के रूप में राजसत्ता का अस्तित्व मिट जाता है।" (एंगेल्स, बेबेल के नाम अपने 28 मार्च 1875 के पत्र में)। "वास्तव में राजसत्ता एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग के दमन के यंत्र के अतिरिक्त और कुछ नहीं होती और यह बात जनवादी जनतंत्र के बारे में भी उतनी ही सच है, जितनी राजतंत्र के बारे में।" ('फ्रांस में गृहयुद्ध' नामक मार्क्स की रचना में एंगेल्स की भूमिका[33]) सार्विक मताधिकार "मजदूर वर्ग की परिपक्वता का मापदंड है। आजकल की राजसत्ता में वह इसके अतिरिक्त न तो और कुछ हो सकता है और न कभी होगा।" (राजसत्ता संबंधी अपनी कृति में एंगेल्स)। श्री काउत्स्की इस प्रस्थापना के पहले भाग को ही लेकर, जो पूंजीपति वर्ग को स्वीकार्य है, बहुत ही नागवार ढंग से चर्वित-चर्वण करते हैं। परन्तु जहां तक दूसरे भाग का सवाल है, जिसे हमने मोटे अक्षरों में छापा है और जो पूंजीपति वर्ग को स्वीकार्य नहीं है, गद्दार काउत्स्की उसे चुपचाप टाल जाते हैं!)। "कम्यून संसदीय नहीं, बल्कि कामकाजी संस्था होनेवाली थी, जो एक साथ ही कार्यकारिणी भी होती और विधायिनी भी...हर तीन या छः वर्षों में एक बार इस बात का फैसला करने के बजाय कि शासक वर्ग का कौन सा सदस्य संसद में जनता का प्रतिनिधित्व तथा दमन करेगा (ver- und zertreten), सार्विक मताधिकार का उद्देश्य कम्यूनों में संगठित जनता की उसी प्रकार सेवा करना था, जिस तरह वैयक्तिक मताधिकार अपने कारोबार के लिए मजदूरों, फोरमैनों और मुनीमों की खोज करनेवाले हर मालिक की सेवा करता है।" (मार्क्स, पेरिस कम्यून के बारे में अपनी रचना 'फ्रांस में गृहयुद्ध' में)[35]।

इनमें से प्रत्येक प्रस्थापना, जिन्हें महापंडित श्री काउत्स्की बहुत अच्छी तरह जानते हैं, उनके मुंह पर एक तमाचा है और उनकी गद्दारी को नग्न रूप में पेश कर देती है। अपनी पुस्तिका में कहीं भी काउत्स्की ने इस बात को प्रकट नहीं किया है कि वे इन सत्यों को रत्ती भर भी समझते हों। उनकी पूरी पुस्तिका मार्क्सवाद का केवल मुंह चिढ़ाती है!

आधुनिक राज्यों के बुनियादी कानूनों को ले लीजिये, उनकी प्रशासन-व्यवस्था को ले लीजिये, सभा करने के अधिकार या अखबारों की स्वतंत्रता को ले लीजिए, "कानून की दृष्टि में सभी नागरिकों की बराबरी" को ले लीजिये और आपको हर कदम पर पूंजीवादी जनवाद की मक्कारी का प्रमाण दिखायी देगा, जिससे हर ईमानदार तथा वर्ग-चेतन मजदूर परिचित है। एक भी राज्य ऐसा नहीं है, चाहे वह जितना भी जनवादी क्यों न हो, जिसके संविधान में ऐसे चोर-दरवाजे या शर्तें न रखी गयी हों, जिनसे पूंजीपति वर्ग के लिए इस बात का आश्वासन हो जाये कि यदि "सार्वजनिक सुव्यवस्था भंग हो" और वस्तुतः यदि शोषित वर्ग अपनी दासता की स्थिति को "भंग करे" और दासता के प्रतिकूल आचरण करने की कोशिश करे, तो पूंजीपति वर्ग मजदूरों के खिलाफ फौजें भेज सकता है, मार्शल-लॉ की घोषणा कर सकता है, इत्यादि। काउत्स्की निर्लज्जता से पूंजीवादी जनवाद को बना-संवार कर पेश करते हैं और इस बात का उल्लेख करना भूल जाते हैं कि उदाहरण के लिए अमेरिका या स्विट्जरलैंड के सबसे अधिक जनवादी तथा जनतंत्रवादी पूंजीपति हड़ताल करनेवाले मजदूरों के साथ क्या सलूक करते हैं।[1]

ओह, बुद्धिमान और ज्ञानी काउत्स्की इन बातों के बारे में एक शब्द भी नहीं कहते! वे विद्वान राजनीतिज्ञ यह भी नहीं समझते कि इस सवाल पर चुप रहना पाजीपन है। वे मजदूरों को इस प्रकार की बच्चों जैसी कहानियां सुनाना ज्यादा पसंद करते हैं कि जनवाद का अर्थ है "अल्पसंख्यकों का संरक्षण"। बात समझ में नहीं आती, पर है सच! ईसवी सन 1918 की गर्मियों में विश्वव्यापी साम्राज्यवादी नरमेध और संसार के सभी "जनतंत्रों" में अन्तर्राष्ट्रीयतावादी अल्पसंख्यकों की गर्दन-घोटाई के इस पांचवें वर्ष में (अर्थात उन अल्पसंख्यकों की, जिन्होंने रेनोदिल तथा लॉन्गे, शीदेमान तथा काउत्स्की, हेंडेरसन और वेब जैसे लोगों की तरह समाजवाद के साथ निन्दनीय ढंग से विश्वासघात नहीं किया है), विद्वान श्री काउत्स्की मधुर स्वर में, बहुत ही मधुर स्वर में, "अल्पसंख्यकों के संरक्षण" का गुणगान करते हैं। जिन लोगों को दिलचस्पी हो, वे इस बात को श्री काउत्स्की की पुस्तिका के 15वें पृष्ठ पर पढ़ सकते हैं और 16वें पृष्ठ पर ये विद्वान...महानुभाव आपको अठारहवीं शताब्दी में इंगलैंड के व्हिग दल और टोरी दल[36] के बारे में बताते हैं!

वाह, कैसी विद्वत्ता है! पूंजीपति वर्ग की कैसी परिष्कृत चाटुकारिता है! पूंजीपतियों के आगे नाक रगड़ने का, उनके तलवे चाटने का कितना सभ्य ढंग है! यदि मैं क्रुप्प या शीदेमान, या क्लीमेंसो या रेनोदिल होता, तो मैं श्रीमान काउत्स्की को लाखों का पुरस्कार देता, छद्म चुम्बनों की बौछार कर देता, मजदूरों के सामने उनकी प्रशंसा करता और उनके जैसे "मानवीय" लोगों के साथ "समाजवादी एकता" का अनुरोध करता। सर्वहारा वर्ग के अधिनायकत्व के खिलाफ पुस्तिकाएं लिखना, अठारहवीं सदी के इंग्लैंड के व्हिग दल तथा टोरी दल की बात करना, जनवाद का अर्थ "अल्पसंख्यकों का संरक्षण" बताना और अमेरिका के "जनवादी" जनतंत्र में अन्तर्राष्ट्रीयतावादियों के खिलाफ संगठित लूट-मार के बारे में चुप रहना—क्या यह टुकड़खोरों की तरह पूंजीपति वर्ग की सेवा करना नहीं है?

विद्वान श्री काउत्स्की एक "छोटी-सी बात" को "भूल गये हैं", शायद संयोगवश भूल गये हैं; वह बात यह है कि पूंजीवादी जनवाद में शासक पार्टी अल्पसंख्यकों के संरक्षण का सिद्धान्त केवल दूसरी पूंजीवादी पार्टी पर ही लागू करती है, जबकि सभी गंभीर, गूढ़ तथा बुनियादी सवालों के सिलसिले में सर्वहारा वर्ग को "अल्पसंख्यकों के संरक्षण" के बजाय मार्शल-लॉ या संगठित हत्याकाण्ड मिलते हैं। जहां पर जनवाद जितना ही विकसित होता है, वहां पूंजीपति वर्ग के लिए खतरनाक किसी गहरे राजनैतिक विरोध के प्रसंग में संगठित हत्याकांडों और गृहयुद्ध की संभावना उतनी ही अधिक तात्कालिक हो जाती है। विद्वान श्री काउत्स्की जनतांत्रिक फ्रांस के ड्राइफस के मुकदमे के प्रसंग में [37], अमरीका के जनवादी जनतंत्र में हब्शियों तथा अन्तर्राष्ट्रीयतावादियों की निर्मम हत्याओं के प्रसंग में, जनवादी इंगलैंड में आयर्लैंड तथा अल्स्टर के प्रसंग में [38], रूस के जनवादी जनतंत्र में अप्रैल 1917 में बोल्शेविकों के सताये जाने और उनके खिलाफ बड़े पैमाने पर संगठित की गयी मार-पीट के प्रसंग में, पूंजीवादी जनवाद के इस "कानून" का अध्ययन कर सकते थे। मैंने जान-बूझकर युद्ध-काल के ही नहीं, बल्कि ऐसे उदाहरण भी चुने हैं, जो युद्ध से पहले के, शांति-काल के हैं। परन्तु मृदुभाषी श्री काउत्स्की बीसवीं शताब्दी की इन घटनाओं की ओर से आंखें मूंदकर बहुत खुश हैं और उसके बजाय मजदूरों को अठारहवीं सदी के व्हिग दल तथा टोरी दल के बारे में आश्चर्यजनक हद तक नयी, बेहद दिलचस्प, असाधारण रूप से शिक्षाप्रद तथा अविश्वसनीय हद तक महत्वपूर्ण बातें बताते हैं।

पूंजीवादी संसद को ले लीजिये। क्या यह संभव है कि विद्वान काउत्स्की ने यह बात कभी सुनी ही न हो कि जनवाद का विकास जितने ही अधिक उच्च स्तर का होता है, पूंजीवादी संसदों को उतना ही अधिक सराफा-बाजार और बैंकपति अपने अधीन कर लेते हैं? इसका मतलब यह नहीं है कि हमें पूंजीवादी संसदों का फायदा नहीं उठाना चाहिए (दुनिया की किसी भी और पार्टी की अपेक्षा बोल्शेविकों ने उनका बेहतर ढंग से फायदा उठाया, क्योंकि 1912-1914 में हमने चौथी दूमा में मजदूरों के सभी निर्वाचक मंडलों में जीत हासिल कर ली)। लेकिन इसका यह मतलब जरूर है कि केवल एक उदारतावादी ही पूंजीवादी संसद-पद्धति की ऐतिहासिक परिसीमितता को और उसके प्रतिबंधित स्वरूप को भूल सकता है, जैसे काउत्स्की भूल गये हैं। सर्वाधिक जनवादी पूंजीवादी राज्य में भी उत्पीड़ित जन-साधारण को हर कदम पर पूंजीपतियों के "जनवाद" द्वारा उद्घोषित औपचारिक समानता और उन हजारों वास्तविक परिसीमाओं तथा तिकड़मों के बीच स्पष्ट अन्तर्विरोध का सामना करना पड़ता है, जो सर्वहाराओं को उजरती मजदूर बना देती हैं। ठीक यही अन्तर्विरोध है, जो पूंजीवाद के सड़ेपन, झूठ और मक्कारी के बारे में जन-साधारण की आंखें खोल रहा है। यही वह अन्तर्विरोध है, जिसकी कलई समाजवादी आंदोलनकर्ता तथा प्रचारक लगातार जन-साधारण के सामने खोल रहे हैं ताकि वे उन्हें क्रांति के लिए तैयार कर सकें! लेकिन जब क्रांतियों का युग आरम्भ हो चुका है, तब काउत्स्की उसकी ओर से मुंह फेर लेते हैं और मरणासन्न पूंजीवादी जनवाद का गुणगान करने लगते हैं।

सर्वहारा जनवाद ने, जिसका एक रूप सोवियत सत्ता है, जनसंख्या के ठीक विशाल बहुमत के लिए, ठीक शोषित तथा श्रमिक जनता के लिए जनवाद को एक ऐसा विकास तथा विस्तार प्रदान किया है, जैसा अब तक दुनिया में पहले कभी नहीं हुआ था। जनवाद के बारे में एक पुस्तिका लिखना, जैसा कि काउत्स्की ने किया है और उसमें अधिनायकत्व के बारे में केवल दो पृष्ठ और "शुद्ध जनवाद" के बारे में बीसियों पृष्ठ लिखना और इस बात को देख भी न सकना, इसका मतलब विषय को उदारतावादी ढंग से पूरी तरह तोड़-मरोड़ कर पेश करना है।

वैदेशिक नीति को ले लीजिये। किसी भी पूंजीवादी राज्य में, सबसे अधिक जनवादी

(शेष पृष्ठ 7 पर)

वेनेजुएला पर अमेरिकी हमला..

(पृष्ठ 1 का शेष)

नई दिल्ली : साम्राज्यवादी अमेरिका द्वारा वेनेजुएला पर किये गये कायराना हमले के खिलाफ 4 जनवरी को अखिल भारतीय विरोध दिवस पर एसयूसीआई (सी) की दिल्ली राज्य कमेटी ने देश की राजधानी में विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी जंतर मंतर पर एकत्र हुए।

इस मौके पर पार्टी के राज्य सचिव कॉमरेड प्राण शर्मा, कॉमरेड इंद्र जीत, कॉमरेड रितु कौशिक, कॉमरेड सतीश पवार, कॉमरेड अद्रिका व कॉमरेड मोहित शर्मा ने संबोधित किया।

पटना (बिहार) : अमेरिकी साम्राज्यवादियों द्वारा वेनेजुएला पर बर्बर हमले के खिलाफ एसयूसीआई (सी) ने 4 जनवरी को यहां पटना जंक्शन गोलंबर पर विरोध प्रदर्शन किया।

विरोध प्रदर्शन में लोग 'युद्ध रोको', 'पूंजीवाद-साम्राज्यवाद मुर्दाबाद', 'अमेरिकी साम्राज्यवाद वेनेजुएला से तुरंत दूर हटो', 'युद्ध के खिलाफ जुझारू शांति आंदोलन तेज करो', 'जनवाद पसंद, शांति पसंद लोग वेनेजुएला के साथ खड़े हों' आदि नारे लगा रहे थे। जंक्शन गोलंबर पर एक विरोध सभा की गई।

सभा को संबोधित करने वालों में एसयूसीआई (सी) के बिहार राज्य कमेटी सदस्य कॉमरेड सूर्यकर जितेंद्र, पटना ग्रामीण जिला सचिव कॉमरेड अनामिका कुमारी, कॉमरेड अपराजिता अर्चना के साथ-साथ एआईडीएसओ के राज्य अध्यक्ष कॉमरेड विजय कुमार एवं एआईडीवाईओ के राज्य अध्यक्ष कॉमरेड सरोज कुमार सुमन प्रमुख थे।

भोपाल (मध्य प्रदेश) : साम्राज्यवादी अमरीका द्वारा वेनेजुएला पर हमले के खिलाफ एसयूसीआई (सी) की तरफ से 4 जनवरी को मप्र की राजधानी भोपाल में जिंसी चौराहे पर विरोध प्रदर्शन किया गया।

पार्टी की राज्य कमेटी सदस्य कॉमरेड रचना अग्रवाल ने सभा को संबोधित किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में शांतिपसंद लोग शामिल हुए।

ग्वालियर (म.प्र.) : वेनेजुएला पर अमेरिकी हमले के विरोध में एसयूसीआई (सी) ने 8 जनवरी को फूल बाग चौराहे पर प्रदर्शन किया।

इस मौके पर कॉमरेड रूपेश जैन ने कहा कि वेनेजुएला पर किया गया सैन्य हमला अत्यंत निन्दनीय है। साम्राज्यवादी देश अमेरिका वेनेजुएला के तेल भण्डारों पर कब्जा करना चाहता है, इसलिए कई बहाने बना कर उसने वेनेजुएला पर युद्ध थोप दिया है और एक सम्प्रभु राष्ट्र की संप्रभुता खत्म कर दी है। इतना ही नहीं, अब वह कोलंबिया, क्यूबा, ग्रीनलैंड आदि देशों पर भी हमले की तैयारी कर रहा है। दुनिया में सभी जगह प्राकृतिक संसाधनों पर कब्जे के लिए दुनिया के उद्योगपति लालायित हैं, इसलिए वे दुनिया पर युद्ध थोप रहे हैं।

पार्टी की जिला कमेटी सदस्य कॉमरेड श्रुति शिवहरे और कॉमरेड विद्या ने भी अपने विचार रखे।

अहमदाबाद (गुजरात) : वेनेजुएला पर अमेरिकी हमले के खिलाफ 5 जनवरी को अहमदाबाद में विरोध प्रदर्शन किया गया।

रायपुर (छत्तीसगढ़) : वेनेजुएला में साम्राज्यवादी अमेरिकी सैन्य हस्तक्षेप के खिलाफ 6 जनवरी को यहां प्रदर्शन हुआ।

अनंतपुर (आंध्र प्रदेश) : एसयूसीआई (सी) ने 4 जनवरी को यहां के घंटा घर पर विरोध कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें वेनेजुएला पर अमेरिकी साम्राज्यवादियों के मिलिट्री हमले की निंदा की गई।

विजयवाड़ा (आंध्र प्रदेश) : वेनेजुएला पर अमेरिकी साम्राज्यवादियों के सैन्य हमले की निंदा करते हुए लेनिन सेंटर, विजयवाड़ा में एसयूसीआई (सी) पार्टी ने विरोध प्रदर्शन किया। पार्टी के राज्य सचिव और केन्द्रीय कमेटी सदस्य कॉमरेड बी. एस. अमरनाथ ने सभा को संबोधित किया।

बदलापुर, जौनपुर (उ.प्र.) : साम्राज्यवादी अमेरिका द्वारा वेनेजुएला पर बर्बर हमले करने और उसके राष्ट्रपति निकोलस मादुरो व उनकी पत्नी का अपहरण किये जाने के खिलाफ एसयूसीआई (सी) पार्टी के देशव्यापी विरोध सप्ताह मनाने के आह्वान पर पार्टी की जौनपुर जिला कमेटी की ओर से 8 जनवरी को बदलापुर चौक पर विरोध प्रदर्शन किया गया।

विरोध प्रदर्शन को पार्टी के जौनपुर जिला सचिव कॉमरेड अशोक कुमार खरवार के अलावा कॉमरेड प्रमोद कुमार शुक्ल, राजेंद्र प्रसाद तिवारी, मिथिलेश कुमार मौर्य व दिलीप कुमार खरवार ने सम्बोधित किया।

अमरोहा (उत्तरप्रदेश) : वेनेजुएला पर अमेरिकी हमले के खिलाफ एसयूसीआई (सी) पार्टी ने 10 जनवरी को अमरोहा कलेक्ट्रेट पर रोष प्रदर्शन किया।

जमशेदपुर (झारखंड) : वेनेजुएला में अमरीकी साम्राज्यवादी हमले के खिलाफ 7 जनवरी को जमशेदपुर में विरोध प्रदर्शन किया गया।

पिलानी (राजस्थान) : वेनेजुएला पर अमेरिकी हमले के खिलाफ एसयूसीआई (सी) ने पिलानी तालाब बस स्टैंड पर डोनाल्ड ट्रंप का पुतला जलाया।

सोनीपत (हरियाणा) : अमेरिकी साम्राज्यवादियों द्वारा वेनेजुएला पर किये गए सैन्य हमले के विरोध में एसयूसीआई (सी) ने 6 जनवरी को शहर के महलाना चौक से नारे लगाते हुए छोटूराम चौक पर विरोध प्रदर्शन किया और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का पुतला फूंका।

प्रदर्शनकारियों को पार्टी के राज्य सचिवमंडल सदस्य कॉमरेड ईश्वर सिंह राठी ने संबोधित किया।

भिवानी (हरियाणा) : एसयूसीआई (सी) ने 8 जनवरी को शहर में दिनोद गेट पर विरोध प्रदर्शन कर अमेरिकी साम्राज्यवादियों द्वारा वेनेजुएला पर किये गए सैन्य हमले पर रोष जातया और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का पुतला फूंका।

इस मौके पर पार्टी के जिला सचिव कॉमरेड रोहतास सिंह सैनी और जिला कमेटी सदस्य कॉमरेड राजकुमार बासिया ने संबोधित किया।

उन्होंने वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो व उनकी पत्नी को तुरंत रिहा करने की पुरजोर मांग की। उन्होंने साम्राज्यवाद-विरोधी, युद्ध-विरोधी और शांतिप्रिय लोगों से अमेरिका के इस कायराना हमले के खिलाफ एकजुट होकर आवाज उठाने और वेनेजुएला के साथ खड़े होने की अपील की।

विरोध प्रदर्शन में कई अन्य लोग शामिल हुए।

पटना

पिलानी

रायपुर

बहादुरगढ़

भिवानी

बदलापुर

अहमादाबाद

बेंगलुरु

भोपाल

ग्वालियर

जमशेदपुर चेन्नई

अनंतपुर

विजयवाडा

अमरोहा

सोनीपत

गुरुग्राम

नारनौल

बुढ़लाडा

सावित्रीबाई फुले की जयंती मनायी

रायपुर (छत्तीसगढ़): एआईडीएसओ की कुरुद् कॉलेज कमेटी द्वारा देश की प्रथम महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले की जयंती सम्मानपूर्वक मनायी गयी।

इस मौके पर कॉलेज के प्राध्यापक व छात्र-छात्राएं शामिल हुए।

एआईडीएसओ, मध्य प्रदेश का तीसरा राज्य स्तरीय छात्र सम्मेलन संपन्न

भोपाल (मध्य प्रदेश) : छात्र संगठन एआईडीएसओ का तृतीय राज्य स्तरीय छात्र सम्मेलन राजधानी भोपाल में 3 और 4 जनवरी को संपन्न हुआ। यह सम्मेलन नवजागरण काल के अग्रदूत ज्योतिबा फुले के 200वें जयंती वर्ष और काकोरी एक्शन के शहीदों की याद को समर्पित था।

सम्मेलन की शुरुआत झालावाड़ जिले में स्कूल भवन के नीचे दबकर जान गवाने वाले छात्रों व इंदौर के भागीरथ पूरा में दूषित पीने के पानी के कारण मरने वाले लोगों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त करते हुए एक शोक प्रस्ताव भी रखा गया।

सम्मेलन की स्वागत समिति में अध्यक्ष सेवानिवृत्त बैंक प्रबंधक शशि भूषण यादव, यूनियन नेता जी सी जोशी के अलावा शहर के कई वरिष्ठ प्रबुद्ध जन शामिल थे।

मुख्य वक्ता एआईडीएसओ के महासचिव कॉमरेड शिवाशीष प्रहराज ने अपने भाषण में एनईपी-2020 के पीछे सरकारों के असली मकसद का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि किस तरह से यह नीति सार्वजनिक शिक्षा, संस्कृति और शिक्षा के लोकतांत्रिक सार को नष्ट करने के मंसूबे से बनायी गयी है। संगठन के अध्यक्ष कॉमरेड सौरव घोष भी मंच पर मौजूद थे।

सम्मेलन में एसयूसीआई (सी) पार्टी से कॉमरेड मुदित भटनागर ने राज्य में 94000 हजार सरकारी स्कूलों को बंद करने के खिलाफ एक जोरदार छात्र आंदोलन छेड़ने की अपील की। साथ-साथ शासक वर्ग द्वारा फैलायी जा रही सांप्रदायिक नफरत के खिलाफ आवाज बुलंद करते हुए धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक व्यवस्था बनाने के संघर्ष को तेज करने पर भी जोर दिया।

सम्मेलन में कर्नाटक से पधारीं अश्विनी ने कर्नाटक राज्य में चलाये जा रहे स्कूल बचाओ आंदोलन के अनुभव साझा किये। हरियाणा से आये कॉमरेड उमेश मौर्य ने भी अपने संबोधन में आंदोलन की जरूरत पर बल देते हुए प्रतिनिधियों से प्रदेश के हर गांव-शहर में स्कूल बचाओ, शिक्षा बचाओ कमेटियों का निर्माण करते हुए आंदोलन को मजबूत करने की अपील की।

मुख्य राजनीतिक प्रस्ताव के अलावा सम्मेलन में 4 प्रस्ताव और पारित किये गए : 94000

भोपाल: छात्र सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए कॉमरेड शिवाशीष प्रहराज

सरकारी स्कूलों को बंद करने की नीति के खिलाफ, पर्यावरण संरक्षण की मांग, महिलाओं व बच्चियों में बढ़ते अपराधों के खिलाफ, चिकित्सा शिक्षा में व्याप्त समस्याएं। सभी प्रस्तावों पर छात्र प्रतिनिधियों द्वारा बात रखी गई ।

दो दिवसीय सम्मेलन में दो विशेष सत्र रखे गए। एक सत्र, एआईडीएसओ के पूर्व नेताओं के साथ था, जिसमें उन्होंने मध्य प्रदेश में एआईडीएसओ बनाने और विस्तारित करने में आयी कठिनाइयों और कठिन संघर्षों के अपने अनुभव साझा किये, जो काफी शिक्षाप्रद थे। 3 जनवरी की शाम को आयोजित सांस्कृतिक सत्र में विभिन्न जिलों के प्रतिनिधियों ने झालावाड़ घटना का चित्रण, शैक्षणिक समस्याएं, रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खान की दोस्ती और आजादी की लड़ाई में भूमिका पर नाटक, महिलाओं के खिलाफ अपराधों पर नृत्य-नाटिका, सावित्री बाई फुले का संघर्ष आदि सामाजिक, सांस्कृतिक व शैक्षणिक समस्याओं को लेकर अपनी प्रस्तुतियां दीं।

सम्मेलन के अंत मे नई राज्य परिषद का चुनाव किया गया। इसमें कॉमरेड श्रुति शिवहरे और कॉमरेड नारायण सिंह चंदेल को क्रमशः राज्य अध्यक्ष और राज्य सचिव चुना गया। कॉन्फ्रेंस में 20 सदस्यीय कार्यकारिणी और 138 सदस्यीय राज्य परिषद चुनी गई। सभी प्रतिनिधियों ने सम्मेलन का संदेश पूरे राज्य में फैलाने, सरकारी स्कूलों को बंद करने के खिलाफ आंदोलन खड़ा करने और सरकारी शिक्षा को बचाने की शपथ ली।

इस सम्मेलन में 300 से ज्यादा छात्र प्रतिनिधि बड़े उत्साह के साथ शामिल हुए।

सरकारी शिक्षा बचाने के लिए चेन्नई में कन्वेंशन

चेन्नई (तमिलनाडु) : प्राइमरी से लेकर उच्च शिक्षा तक हजारों शिक्षकों की स्थायी नियुक्ति न होने और सही बुनियादी ढांचे व प्रयोगशालाओं की कमी की वजह से तमिलनाडु की सरकारी शिक्षा व्यवस्था गहरे संकट में है। इस साल 207 सरकारी स्कूल बंद हो गए हैं। मद्रास और मदुरै कामराज यूनिवर्सिटी में काम करने वालों को भी तनख्वाह और पेंशन नहीं मिल रही है, जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आने के बाद सरकारी शिक्षा व्यवस्था की दुर्दशा दिखाता है।

ऐसे में, ऑल इंडिया सेव एजुकेशन कमेटी के तमिलनाडु चौप्टर ने सरकारी शिक्षा सिस्टम को बचाने और जनहित-विरोधी राष्ट्रीय शिक्षा नीति को रद्द करने की मांग को लेकर 27 दिसंबर को चेन्नई में एक कन्वेंशन किया। संगठन के राज्य सचिव प्रोफेसर के. योगराजन ने इसकी अध्यक्षता की। जाने-माने इतिहासकार प्रोफेसर ए. करुणानंदन ने बताया कि कैसे यूजीसी ने भारतीय ज्ञान प्रणाली लाकर शिक्षा के धर्मनिरपेक्ष स्वरूप को साम्प्रदायिक रंग दे दिया। जेएसएस यूनिवर्सिटी के पूर्व प्रिंसिपल एल. जवाहर नेसन ने कहा कि एचईकेआई के जरिये शिक्षा व्यवस्था

का केन्द्रीकरण उच्च शिक्षा की स्वायत्तता के खिलाफ है। यह संस्थानों की खासियत को खत्म कर देता है। ऑल इंडिया सेव एजुकेशन कमेटी के महासचिव प्रोफेसर तरुणकांति नस्कर ने 'जन शिक्षा नीति' को देश के हर वर्ग के शिक्षाविदों और लोगों से मिले भारी समर्थन के बारे में बताया। उन्होंने 24 जनवरी को बैंगलोर में 'जन संसद' को सफल बनाने के लिए पहल करने की अपील की। प्रोफेसर के. कथिरावन, प्रोफेसर पी. राजसिम्हन, प्रोफेसर डी. भास्करन, प्रोफेसर सैमुअल असीर राजा और दूसरे लोगों ने अपनी बातें रखीं। ऑल इंडिया सेव एजुकेशन कमेटी के राज्य अध्यक्ष प्रोफेसर एस. एच. थिलागर ने शिक्षा के निजीकरण, व्यापारीकरण, साम्प्रदायीकरण और केन्द्रीकरण के खिलाफ एकजुट आंदोलन का आह्वान किया।

इंदौर नगर निगम के भागीरथपुरा क्षेत्र में दूषित पानी से हुई मौतों के लिए प्रशासनिक लापरवाही जिम्मेदार -एसयूसीआई (सी)

भोपाल (मध्य प्रदेश) : सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया (कम्युनिस्ट) की मध्य प्रदेश राज्य कमेटी के सचिव कॉमरेड प्रताप सामल ने 1 जनवरी को जारी प्रेस बयान में कहा कि इंदौर नगर निगम के भागीरथपुरा क्षेत्र मे दूषित पानी से हुई मौतों के लिए प्रशासनिक लापरवाही जिम्मेदार है। इंदौर के भागीरथपुरा क्षेत्र में लंबे समय से दूषित और बदबूदार पानी की आपूर्ति के कारण नागरिकों की मौत होना कोई हादसा नहीं, बल्कि नगर निगम और राज्य सरकार की घोर लापरवाही से उपजा प्रशासनिक अपराध है। चार महीनों से लोग गंदा पानी पीने को मजबूर थे, शिकायतों के बावजूद लाइन बदलने और मरम्मत के टेंडर दबाकर रखे गए। नतीजतन, निर्दोष लोगों की जान चली गई। उन्होंने इस जनविरोधी और अमानवीय व्यवस्था के खिलाफ व्यापक जनांदोलन का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि जब तक सुरक्षित पेयजल हर नागरिक के अधिकार के तौर पर सुनिश्चित नहीं होता और दोषियों को सजा नहीं मिलती, तब तक जनता के पास आन्दोलन के सिवा कोई रास्ता नहीं रह जाता है।

एसयूसीआई (सी) ने दूषित पानी से हुई सभी मौतों की न्यायिक जांच कराने, जिम्मेदार अधिकारियों, ठेकेदारों और निर्णय रोकने वालों पर आपराधिक मुकदमे दर्ज करने, मृतकों के परिवारों को पर्याप्त मुआवजा देने और आश्रितों को स्थायी सहायता देने और पूरे शहर की जलापूर्ति व्यवस्था की स्वतंत्र तकनीकी जांच कर सुरक्षित पानी की गारंटी दी जाने की राज्य सरकार से मांग की।

यह घटना तथाकथित "स्वच्छ शहर" के खोखले दावों को उजागर करती है, जहां चमक-दमक के पीछे आम जनता जहरीला पानी पीने को मजबूर है। एसयूसीआई (सी) जनता के साथ खड़ी है और इस अन्याय के खिलाफ जनआंदोलन को और तेज करेगी।

जनजीवन की ज्वलंत समस्याओं के खिलाफ दिल्ली में विरोध प्रदर्शन

दिल्ली की जनता की विभिन्न समस्याओं जैसे डीटीसी बसों की कमी, दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण, कॉलोनियों में फैली गंदगी, पीने के दूषित पानी, घरों पर चलते बुलडोजर, सरकारी स्कूल बंदी, महिलाओं पर बढ़ते अपराध व अन्य जन समस्याओं के खिलाफ एसयूसीआई (सी) की पश्चिमी दिल्ली जिला कमेटी के आह्वान पर 7 जनवरी को दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के आवास के समक्ष विरोध प्रदर्शन किया गया। इस प्रदर्शन में दिल्ली के विभिन्न इलाकों से आए सैकड़ों लोग शामिल हुए।

एनआरएमएल बिहान सक्रिय महिला संघ ने धरना-प्रदर्शन कर सौंपे ज्ञापन

रायपुर (छत्तीसगढ़) : एनआरएलएम बिहान की राज्यभर की सैकड़ों सक्रिय महिलाओं ने 5 जनवरी को यहां अपनी मांगो के समर्थन में राज्य स्तरीय प्रदर्शन किया। वे सड़क घेरकर बैठ गयीं और पंचायत मंत्री से मिलकर ज्ञापन देने की जिद पर अड़ गयीं।

धरना-प्रदर्शन को यूनियन की प्रांतीय अध्यक्ष कॉमरेड पदमा पाटिल, महासचिव कॉमरेड बिंदु यादव, सलाहकार कॉमरेड विश्वजीत हारोडे सहित अन्य कई नेताओं ने संबोधित किया।

ये थीं प्रमुख मांगें :

• मानदेय 1910 रुपये मासिक है, जो बहुत कम है। अतः इसे जीने लायक सम्मानजनक स्तर तक बढ़ाया जाए। • व्यक्तिगत मोबाइल में ऑनलाइन काम कराया जा रहा है। अतः सभी कैडरों को मोबाइल या मोबाइल भत्ता व नेट खर्च दिया जाए। • यात्रा भत्ता व

मीटिंग भत्ता व दैनिक भत्ता दिया जाए। • कई वर्षों से कार्यरत सक्रिय महिलाओं को जबरदस्ती कार्य से हटाना पूरी तरह अनुचित और अन्यायपूर्ण है। इसे बंद किया जाए। • यह भी देखने में आया है कि कुछ ब्लॉकों या कुछ क्षेत्रों में यह 1910 रुपया भी 5-6 महीने में एक बार दिया जाता है, वह भी बैंक खाते में नहीं दिया जाता और बेमतलब पैसा काटकर दिया जाता है। मानदेय प्रतिमाह दिया जाए। इसे सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर किया जाए। • नियुक्ति पत्र दिया जाए। • नियमितीकरण किया जाए।

12 फरवरी की देशव्यापी आम हड़ताल को सफल बनाने के लिए मिड डे मील कर्मियों ने कमर कसी

मड़वन (बिहार) : एआईयूटीयूसी से संबद्ध बिहार विद्यालय रसोईया यूनियन की बैठक 29 दिसंबर को मुजफ्फरपुर जिले के मड़वन प्रखंड स्थित जानकी उच्च विद्यालय में माला देवी की अध्यक्षता में हुई।

इसमें 12 फरवरी 2026 की देशव्यापी आम हड़ताल को सफल बनाने पर विचार-विमर्श किया गया। बैठक को एआईयूटीयूसी के सदस्य कॉमरेड उमाकांत कुमार तथा बिहार विद्यालय रसोईया यूनियन प्रखंड सचिव /राज्य सहसचिव कॉमरेड सुनैना देवी आदि ने संबोधित किया।

एआईएमएसएस का पूर्वी सिंहभूम जिला महिला सम्मेलन सम्पन्न

जमशेदपुर (झारखंड) : महिलाओं और बच्चियों पर बढ़ते अपराध, शराब, नशीले पदार्थों और पार्नोग्राफी पर रोक लगाने की मांग को लेकर 4 जनवरी को यहां ऑल इण्डिया महिला सांस्कृतिक संगठन (एआईएमएसएस) का पूर्वी सिंहभूम जिला सम्मेलन सम्पन्न हुआ।

PRGI Regn. No. 43022

सोशल मीडिया के बारे में

कॉमरेड प्रभास घोष

(कोलकाता में 10 नवंबर 2025 को हुई सोशल मीडिया वर्कशॉप में दिया गया भाषण)

कॉमरेडो,

आप सभी को मेरा क्रांतिकारी अभिनन्दन।

हमारी पार्टी, भारतीय सर्वहारा वर्ग की क्रांतिकारी पार्टी के सोशल मीडिया को विकसित करने की आपकी हिम्मत वाली पहल का मैं स्वागत करता हूं। कॉमरेडो, इस विषय पर चर्चा करने के लिए मुझे लगभग एक ऐसे क्षेत्र में जाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, जहां मैंने पहले कभी कदम नहीं रखा था। मुझे इस बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं है।

चर्चा को समेटने का मतलब है, चर्चा के सभी बिन्दुओं को संक्षेप में बताना और हमारे कामों के बारे में एक मार्गदर्शन देना, जबकि मैंने चर्चा में बिल्कुल भी हिस्सा नहीं लिया है। फिर भी मैं आपके सामने कुछ शब्द बोलना चाहता हूं।

असल में, मुझे इस सेलफोन का इस्तेमाल सिर्फ कॉमरेडों से संपर्क करने के लिए करने की आदत है। कॉमरेड भी मुझसे सेलफोन पर संपर्क करते हैं। कभी-कभी मैं कुछ गाने सुनता हूं। कभी-कभी मैं कुछ खबरें या आंदोलन देखता हूं। यह मेरा नॉर्मल तरीका है। यह सच है कि सोशल मीडिया प्रचार-प्रोपेगैंडा का एक ताकतवर हथियार बन गया है। और यह भी सच है कि बुर्जुआ पार्टियों के साथ-साथ बुर्जुआ वर्ग के हितों के लिए काम करने वाली ताकतें इस सोशल मीडिया को कंट्रोल करती हैं। वे इसका इस्तेमाल अपने वर्ग के फायदे के लिए करती हैं। अब क्रांतिकारी सर्वहारा के नजरिये से इसका मुकाबला करने, बुर्जुआ प्रचार-प्रोपेगैंडा का पर्दाफाश करने, लोगों के दिमाग को इसके बुरे असर से मुक्त करने की जरूरत है। तब, इस फील्ड में भी यह एक वर्ग संघर्ष है। मैंने सुना है कि कॉमरेड तकनीक से लैस हैं। मुझे वरिष्ठ नेताओं ने बताया है कि कई लोग इस क्षेत्र में भी आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन सिर्फ तकनीकी जानकारी काफी नहीं है। एक अच्छा प्रचारक बनने के लिए, यह बहुत जरूरी है कि कोई सैद्धांतिक, राजनैतिक, सांगठनिक और सांस्कृतिक तौर पर लैस हो। यह एक शर्त है। अत: जो कॉमरेड वर्ग संघर्ष में लगे हैं, दबे-कुचले लोगों के प्रति सरोकार महसूस करते हैं, वही अच्छे प्रचारक बन सकते हैं। यह भावना अमूर्त रूप में नहीं, बल्कि ठोस रूप में होनी चाहिए। मेरा दिल, मेरा विवेक हमेशा उन लोगों का दर्द महसूस करे, जो फुटपाथ पर रहते हैं, सड़कों पर रहते हैं, भीख मांगते हैं और जो जिंदा रहने के लिए रो रहे हैं। मैं उनके प्रति सरोकार महसूस करता हूं। मेरा मन हमेशा उसमें डूबा रहता है। उसके लिए मैं मुक्ति का रास्ता खोजता हूं। यही चीज किसी को क्रांतिकारी, एक अच्छा कम्युनिस्ट बनाती है। उसके लिए, मुझे मार्क्सवाद-लेनिनवाद-शिवदास घोष विचार से क्रांतिकारी ज्ञान हासिल करने की जरूरत है। यह संघर्ष किसी खास समय, खास घंटे या खास पल के लिए नहीं, बल्कि एक लगातार संघर्ष होना चाहिए। मन हमेशा उसमें डूबा रहना चाहिए। नहीं तो, तकनीकी तौर पर कोई परिपक्व हो सकता है, लेकिन उससे कुछ नहीं होगा।

प्रस्तुति जिंदादिल और ठोस होनी चाहिए, जो लोगों को शिक्षित करे, उन्हें ज्ञान दे, उन्हें प्रेरित करे, उन्हें अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए एकजुट होने और संगठित करने में मदद करे। इसलिए उन्हें सिर्फ एक कमरे में नहीं रहना चाहिए, बल्कि इस फील्ड में योद्धाओं के तौर पर उन्हें वर्ग संघर्ष में, सड़क की लड़ाई में शामिल होना चाहिए।

अब, मुझे इस मीटिंग में सैद्धांतिक रूप से यह समझाने की जरूरत नहीं है कि पूरी दुनिया में क्या हो रहा है, क्योंकि आप सब विकसित कॉमरेड हैं। आप इसे देख रहे हैं। दो साम्राज्यवादी ताकतें, अमेरिकी साम्राज्यवाद और चीनी साम्राज्यवाद एक-दूसरे से लड़ रहे हैं। दुनिया में दूसरे नंबर की साम्राज्यवादी ताकतें और तीसरे नंबर की साम्राज्यवादी ताकतें भी हैं। भारत तीसरी कैटेगरी में आता है। दूसरे नंबर की साम्राज्यवादी ताकतें यूके, फ्रांस, जर्मनी और जापान जैसे विकसित देश हैं। ट्रेड वॉर एक प्रॉक्सी वॉर है, लेकिन यह एक युद्ध है—आर्थिक वर्चस्व कायम करने का युद्ध। सशस्त्र युद्ध भी चल रहा है। क्षेत्रीय युद्ध सिर्फ एक क्षेत्र तक ही सीमित नहीं है। सभी महाशक्तियां प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से ऐसे क्षेत्रीय युद्ध कार्रवाइयों में शामिल हैं। यह मत सोचिए कि चीनी साम्राज्यवाद ऐसे युद्ध में शामिल नहीं हैं। वह भी शामिल है। कभी-कभी वह घेराबंदी करके इंतजार कर रहा होता है ताकि जब अमेरिकी साम्राज्यवाद अरब या अफ्रीकी देशों से हट जाए, तो वह सही समय पर दखल दे सके। यही उनका असली फायदा है। मदद देने के नाम पर, वे उन्हें उलझा रहे हैं। ऐसा भी हो रहा है। साम्राज्यवाद-पूंजीवाद अपनी मौत के कगार पर है और बहुत ज्यादा संकट में फंसा हुआ है। बढ़ती नाराजगी बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शनों के जरिये फिर से उभरकर आ रही है, ठीक वैसे ही जैसे लहरें उठती हैं। ऐसे विरोध प्रदर्शन शुरू तो हो रहे हैं, लेकिन फिर शांत हो जा रहे हैं।

यूरोपियन देशों के साथ-साथ दुनिया के कई दूसरे हिस्सों में भी प्रदर्शन, आंदोलन, हड़तालें आजकल आम बात हो गई हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि अमेरिकी लोग अब सड़कों पर उतरकर "नो किंग" (राजा नहीं चाहिए) का नारा लगा रहे हैं। लेकिन उन लोगों में वर्ग नजरिया नहीं है, क्रांतिकारी नजरिया नहीं है। उनके पास उनकी अगुआई करने के लिए कोई सही क्रांतिकारी पार्टी नहीं है। लोगों के विरोध को सही क्रांतिकारी नेतृत्व में उनके तार्किक मंजिल तक पहुंचाना ही आज की जरूरत है। इसलिए जरूरत है कि हमारी पार्टी तेजी से विकसित हो, मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों तरह से। भारत के हालात आप जानते हैं। लोग सभी पार्टियों से नाराज हैं, फ्रस्ट्रेटेड (निराश-हताश) हैं। लेकिन ये पार्टियां वैचारिक और राजनैतिक तौर पर बेनकाब नहीं हुई हैं। यही हालत है। इसलिए इन हालात में, आपको यह समझना होगा कि सोशल मीडिया को हैंडल करने के मामले में आपका क्या काम है।

क्रांतिकारी योद्धाओं के तौर पर आपको एक मकसद के साथ इस क्षेत्र में शामिल होना है। लेकिन मेरा मानना है कि सोशल मीडिया प्रिंट मीडिया का सब्स्टीट्यूट नहीं हो सकता। सोशल मीडिया वह समग्र (कॉम्प्रिहेंसिव) नजरिया नहीं दे सकता, जो प्रिंट मीडिया दे सकता है। प्रिंट मीडिया प्राइमरी हथियार है। सोशल मीडिया एक सहायक हथियार के तौर पर काम कर सकता है। उदाहरण के लिए, हम दीवार पर लिखा एक उद्धरण दे सकते हैं। लेकिन वह किसी खास विषय का सिर्फ एक छोटा-सा पहलू ही बता सकता है। लेकिन वह उस विषय पर एक पूरा नजरिया नहीं दे सकता। मेरे कहने का मतलब यह है कि किसी विषय की गहराई में जाकर उसका सार समझना तभी मुमकिन है, जब आप किसी किताब या लेख को हार्ड कॉपी से या डिजिटल मीडिया के जरिए बार-बार पढ़ें। तभी कोई उस विषय की पूरी समझ बना सकता है। यह मेरी राय है, हालांकि कोई मुझसे अलग राय रख सकता है। हमारी पार्टी के कुछ कॉमरेडों पर भी एक बढ़ती हुई समस्या असर डाल रही है—वह है कॉमरेडों का प्रिंट मीडिया से दूर रहना। पूरी दुनिया में लोग बहुत बेचैन हैं। जैसे-जैसे लोग बेचैन होते हैं, वे अखबार या लेख पढ़ने के लिए एक घंटा, दो घंटे नहीं निकाल पाते। इसलिए किसी चीज को संक्षेप (शॉर्ट) में जानने की आदत दिमाग में आ गई है। कुछ ही मिनटों में कोई किसी सब्जेक्ट के बारे में जानना चाहता है। ऐसा हमेशा समय की कमी की वजह से नहीं होता। ऐसा इसलिए होता है कि उनमें सब्र की कमी होती है। बेचैनी इसका मुख्य कारण है। इसलिए पढ़ने की आदत लगभग खत्म हो रही है। यह दिमाग पर पूंजीवादी हमला है। समाज सड़-गल रहा है, नैतिक ढांचा खराब हो रहा है और सोचने का तरीका गलत दिशा में जा रहा है। इसलिए बेचैनी बढ़ रही है। सोशल मीडिया के आ जाने से जल्दी से नजर डालने या बिना सोचे-समझे देखने की यह आदत प्रिंट मीडिया की जगह ले रही है। इसे बढ़ावा नहीं देना चाहिए। हमें प्रिंट मीडिया पर जोर देना चाहिए। कॉमरेडों को बार-बार किताबें पढ़ने और छपे हुए लेख पढ़ने के लिए सिखाया जाना चाहिए ताकि वे पूरी जानकारी हासिल कर सकें। साथ ही, हमें बातचीत के एक सहायक तरीके के तौर पर सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना चाहिए। मेरा यही मानना है।

और आपको दूसरों की तरह किसी ग्लैमरस अपलोड के पीछे नहीं भागना चाहिए। आपकी कोशिश इसे एकदम सही तरीके से करने की होनी चाहिए, इसे और बेहतर बनाने का तरीका सीखना चाहिए, सोद्देश्यपूर्ण और रचनात्मक तरीके से। लेकिन स्टंट या बहुत ज्यादा कोरियोग्राफ्ड प्रस्तुति से बचना चाहिए। क्योंकि तब फॉर्म कंटेंट पर हावी हो जाएगा। ध्यान से सोचें कि कौन-सी प्रस्तुति क्रांतिकारी मकसद पूरा कर सकती है। आप दूसरों से सीख सकते हैं, लेकिन दूसरों की नकल न करें। सीखने का मतलब है कि मैं यह तय करूं कि दूसरों से क्या ग्रहण करना है और क्या नहीं। नकल का मतलब है आंख बंद करके अंधानुकरण करना। इससे भी आपको बचना चाहिए। यहां एक और जरूरी बात टीम फंक्शनिंग के बारे में है। कुछ लोग इस क्षेत्र में लगे हुए हैं, कुछ दूसरे किसी दूसरी राजनैतिक गतिविधि में लगे हुए हैं। सामूहिक अप्रोच पर आधारित आपकी टीम का काम एक साझे मकसद को पूरा करना होना चाहिए। कोई व्यक्तिगत मकसद पूरा नहीं करना है। कोई व्यक्तिगत महत्वकांक्षा नहीं है, कोई खुद का नाम कमाने और प्रसिद्धि पाने की चाहत नहीं है। यहां भी आपको खुद को बड़ा दिखाने या खुद को बड़ा समझने की आदत से लड़ना होगा। दुश्मन हमारे अंदर ही है, और वह दुश्मन है व्यक्तिवाद। हम सब पूंजीवाद की पैदाइश हैं और इसलिए अक्सर पूंजीवादी व्यक्तिवाद का शिकार हो जाते हैं। हमारी पार्टी के अंदर भी इससे लगातार लड़ना बहुत जरूरी है। सोशल मीडिया टीम में काम करते हुए भी आपको इससे लड़ना होगा। कॉमरेड एक खास राज्य में भी काम कर रहे हैं, अलग-अलग राज्यों में भी या केन्द्रीय स्तर पर भी। लेकिन वे सभी एक ही क्रांतिकारी मकसद को पूरा कर रहे हैं और इसलिए उन्हें एक-दूसरे की मदद करने की जरूरत है। तालमेल का मतलब यांत्रिक तालमेल नहीं है। तालमेल का मतलब है एक-दूसरे की मदद करना, एक-दूसरे से सीखना, किसी चीज को और कैसे विकसित किया जाए, मिलकर कोशिश करके उसे और बेहतर बनाना। और याद रखें, यह एक ऐसा क्षेत्र है, जो आपको क्रांतिकारी आन्दोलन से भी भटका सकता है। मैं फिर से इस बात पर जोर देता हूं कि हमें दबे-कुचले लोगों से लगातार संपर्क बनाये रखना चाहिए, उनकी दुख-तकलीफ को महसूस करना चाहिए, क्रांतिकारी आंदोलन, जन संघर्षों में हिस्सा लेना चाहिए और अपनी-अपनी पार्टी संस्थाओं से लगातार संपर्क बनाये रखना चाहिए। ज्ञान पाने के दो तरीके हैं। एक है सीधा तरीका। आप जनता के साथ होते हैं। आप उन्हें जानते हैं। आप उनके सवालों, उलझनों, निराशाओं को जानते हैं। ये हर इंसान में अलग-अलग भी होते हैं। लेकिन आप इसे सीधे संपर्क से महसूस करते हैं। दूसरा तरीका है अप्रत्यक्ष संपर्क। आप इसे दूसरे कॉमरेडों के जरिये भी जानते हैं। आप उनके साथ बातचीत कर रहे होते हैं और इससे आपको फायदा होता है, आपकी मदद होती है। इसलिए यह अप्रत्यक्ष तरीका भी जरूरी है। दूसरी तकनीकी बातों के बारे में ऐसे नेता हैं, जो आपका मार्गदर्शन और आपकी मदद कर सकते हैं। आपको अपने राज्य या केन्द्र में जो कुछ भी कर रहे हैं, उसके बारे में हमेशा पार्टी से मार्गदर्शन लेना चाहिए।

तथ्य जरूरी नहीं कि सच हों। बुर्जुआ मीडिया भी तथ्य दिखा रहा है। जुल्म, बलात्कार, सामूहिक बलात्कार और भ्रष्टाचार की बातें हो रही हैं। बुर्जुआ मीडिया इन सबको एक ही तरह से दिखा रहा है। आपको भी वही तथ्य दिखाने होंगे, लेकिन अलग तरीके से। सिर्फ तथ्य दिखाना आपका मकसद नहीं होना चाहिए। आपका काम इन तथ्यों में से सच निकालना और लोगों के सामने लाना है। इसका मतलब सिर्फ तथ्य बताना नहीं है। इसे इस तरह से दिखाना चाहिए कि लोग इन समस्याओं की असली वजह समझ सकें। यही आपकी कला होगी। मेरा मतलब है क्रांतिकारी कला। इस तरह से दिखाकर, आप कुछ राजनैतिक शिक्षा भी दे रहे हैं। इसे भी आपको अपने फील्ड में बढ़ाना होगा। राज्य स्तर पर आपको हमेशा राज्य पार्टी नेतृत्व से मार्गदर्शन लेना चाहिए। केन्द्रीय स्तर पर भी आपको केन्द्रीय पार्टी नेतृत्व, खासकर उन नेताओं से लगातार सम्पर्क में रहना चाहिए, जिन्हें इस काम के लिए रखा गया है। सिर्फ फैसला लेने में ही नहीं, बल्कि पेश करने के तरीके में भी, आपको राय लेनी चाहिए। छोटी-छोटी बातों के लिए नहीं, बल्कि एक क्रांतिकारी नजरिये से मार्गदर्शित होने के लिए। आपको पार्टी नेतृत्व से मार्गदर्शन लेना चाहिए। क्या यह साफ है? साथियो, यह विषय ऐसा नहीं है, जिस पर मैं कुछ रोशनी डाल सकूं। बल्कि आप मेरे लिए रोशनी डाल सकते हैं। मैं सदन की चर्चा से चूक गया हूं। फिर भी मुझसे खत्म करने के लिए कहा गया है। चर्चा को फॉलो किये बिना, मैं उसे कैसे समेट सकता हूं? हालांकि मैंने अपने विचार रख दिये हैं और मुझे उम्मीद है कि यह छोटी-सी चर्चा आपके कुछ काम आएगी। ●

पूंजीवादी ....

(पृष्ठ 3 का शेष)

पूंजीवादी राज्य में भी, वह खुले तौर से नहीं चलायी जाती। हर जगह जन-साधारण को धोखा दिया जाता है और जनवादी फ्रांस, स्विट्जरलैंड, अमेरिका तथा इंगलैंड में यह काम दूसरे देशों की तुलना में बेहद व्यापक पैमाने पर और बेहद गूढ़ ढंग से किया जाता है। सोवियत सरकार ने वैदेशिक नीति पर पड़े हुए रहस्य के परदे को क्रांतिकारी ढंग से चीर दिया है। काउत्स्की ने इस बात को नहीं देखा है, वे इस बात की बाबत चुप हैं, हालांकि लूटमार के युद्धों और "प्रभाव-क्षेत्रों के बंटवारे" के लिए (अर्थात पूंजीपति लुटेरों के बीच दुनिया के बंटवारे के लिए) की जानेवाली गुप्त संधियों के युग में यह विषय बुनियादी महत्व का है, क्योंकि इस पर शांति के सवाल का फैसला, करोड़ों लोगों की जिंदगी और मौत का फैसला निर्भर है।

राज्य के संगठन को ले लीजिए। काउत्स्की चुन-चुनकर हर तरह की "छोटी-छोटी बातों" का, यहां तक कि इस दलील का भी जिक्र करते हैं कि सोवियत संविधान के अनुसार चुनाव "अप्रत्यक्ष" रूप से होते हैं, पर वे इस समस्या के सार-तत्व को नहीं पकड़ पाते। वे राज्य के उपकरण के, राज्य की मशीन के वर्गगत स्वरूप को नहीं देख पाते। पूंजीवादी जनवाद के अन्तर्गत पूंजीपति हजारों तरकीबों से "शुद्ध" जनवाद जितना ही अधिक विकसित होता है, ये तरकीबें भी उतनी ही अधिक कुटिलतापूर्ण तथा कारगर होती हैं–जन-साधारण को प्रशासन के काम, अखबारों की स्वतंत्रता, सभा करने के अधिकार आदि से दूर हटाते हैं। सोवियत सत्ता संसार की पहली सत्ता है (या सच पूछा जाये, तो वह दूसरी सत्ता है, क्योंकि पेरिस कम्यून ने भी यही काम करना शुरू किया था) जिसने जन-साधारण को, विशेष रूप से शोषित जन-साधारण को, प्रशासन के काम में जुटाया है। मेहनतकश जन-साधारण को हजारों बाधाओं द्वारा पूंजीवादी संसदों में भाग लेने से रोका जाता है (ये संसदें पूंजीवादी जनवाद के अधीन उठनेवाले महत्वपूर्ण प्रश्नों का फैसला कभी नहीं करतीं; उनका फैसला सराफा बाजार तथा बैंक करते हैं और मजदूर भली-भांति इस चीज को जानते और महसूस करते हैं, देखते और समझते हैं कि पूंजीवादी संसदें ऐसी संस्थाएं हैं, जिनका उनसे कोई संबंध नहीं है, वे पूंजीपति वर्ग द्वारा सर्वहाराओं के उत्पीड़न के साधन हैं, वे एक शत्रु वर्ग की, शोषक अल्पमत की संस्थाएं हैं।

सोवियतें स्वयं मेहनतकश तथा शोषित जन-साधारण का ऐसा प्रत्यक्ष संगठन हैं, जो उन्हें यथासंभव हर प्रकार से स्वयं अपनी राजसत्ता को संगठित करने तथा उसका प्रशासन चलाने में सहायता देता है। इस मामले में मेहनतकशों तथा शोषितों के हिरावल, शहरों के सर्वहारा वर्ग को ही यह सुविधा प्राप्त है कि वह बड़े उद्यमों द्वारा सबसे अच्छे ढंग से संगठित होता है; चुनाव करना और चुनावों पर निगरानी रखना उसके लिए और सभी की अपेक्षा अधिक आसान होता है। सोवियत संगठन अपने आप सभी मेहनतकशों तथा शोषितों को अपने हिरावल के, सर्वहारा वर्ग के इर्द-गिर्द एकताबद्ध होने में सहायता देता है। पुरानी पूंजीवादी मशीनरी– नौकरशाही, सम्पत्ति के विशेषाधिकार, पूंजीवादी शिक्षा तथा सम्पर्कों के विशेषाधिकार आदि (ये वास्तविक विशेषाधिकार उतने ही विविध हैं, जितना पूंजीवादी जनवाद विकसित है) सोवियत ढंग के संगठन में ये सब चीजें मिट जाती हैं। अखबारों की स्वतंत्रता एक ढोंग नहीं रह जाती, क्योंकि छापेखाने और कागज के स्टाक पूंजीपति वर्ग के हाथों से छीन लिये जाते हैं। यही बात सबसे अच्छी इमारतों, महलों, कोठियों और हवेलियों पर भी लागू होती है। सोवियत सत्ता ने एक ही हल्ले में हजारों ऐसी सबसे अच्छी इमारतें शोषकों के हाथों से छीन लीं और इस प्रकार सभाएं करने के अधिकार को–जिसके बिना जनवाद एक धोखा है–जन-साधारण के लिए कई लाख गुना "जनवादी" बना दिया। गैर-स्थानीय सोवियतों के लिए अप्रत्यक्ष चुनावों से सोवियतों की कांग्रेसें करना अधिक आसान हो जाता है, उनसे पूरी मशीनरी कम-खर्च बन जाती है, वह अधिक लोचदार हो जाती है और एक ऐसे समय पर मजदूरों तथा किसानों की पहुंच उन तक ज्यादा आसान हो जाती है, जबकि जीवन में एक उबाल आ रहा है और यह आवश्यक हो जाता है कि कोई भी स्थानीय प्रतिनिधि बहुत जल्दी उसके पद से हटाकर वापस बुलाया जाए या उसे सोवियतों की आम कांग्रेस में प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया जाए।

सर्वहारा जनवाद किसी भी पूंजीवादी जनवाद की तुलना में कई लाख गुना अधिक जनवादी है; सोवियत सत्ता अधिक से अधिक जनवादी पूंजीवादी जनतंत्र की तुलना में भी कई लाख गुनी अधिक जनवादी है।

इस बात को न देख सकने का मतलब यह है कि आदमी या तो जान-बूझकर पूंजीपति वर्ग की सेवा करता है या राजनैतिक दृष्टि से बिल्कुल मुर्दा है, वह पूंजीवादी पुस्तकों के गर्द भरे पृष्ठों के पीछे से वास्तविक जीवन को नहीं देख सकता, उसमें पूंजीवादी जनवादी पूर्वाग्रह कूट-कूट कर भरे हुए हैं और इस प्रकार उसने वस्तुपरक दृष्टि से अपने आपको पूंजीपति वर्ग का टुकड़खोर बना लिया है।

इस बात को वही आदमी नहीं देख सकता, जो उत्पीड़ित वर्गों के दृष्टिकोण से इस प्रश्न को प्रस्तुत करने में असमर्थ है कि :

क्या संसार में एक भी देश, अधिक से अधिक जनवादी पूंजीवादी देशों में से भी कोई देश ऐसा है, जिसमें औसत आम मजदूर को, औसत ग्रामीण खेत-मजदूर को या गांव के आम अर्ध-सर्वहारा को (अर्थात उत्पीड़ित जन-साधारण के, जनसंख्या के विशाल बहुमत के प्रतिनिधि को) सबसे अच्छी इमारतों में सभाएं करने की स्वतंत्रता जैसी कोई चीज नसीब हो? जहां उसे अपने विचारों को व्यक्त करने और अपने हितों की रक्षा करने के लिए सबसे बड़े छापेखाने और कागज के सबसे बड़े भंडार इस्तेमाल करने की आजादी, स्वयं अपने वर्ग के पुरुष-स्त्रियों को तरक्की देकर राज्य प्रशासन चलाने और राज्य को "उचित रूप में ढालने" के काम में लगाने की आजादी उसी तरह हो जैसी सोवियत रूस में है?

यह सोचना हास्यास्पद बात है कि श्रीमान काउत्स्की किसी भी देश में हजार प्रबुद्ध मजदूरों या खेत-मजदूरों में से एक भी ऐसा आदमी पा सकते हैं, जिसे इस प्रश्न के उत्तर के बारे में कोई भी संदेह हो। पूंजीवादी अखबारों में सत्य के छोटे-छोटे अंशों को जिस तरह स्वीकार किया जाता है उसे सुनकर पूरी दुनिया के मजदूरों के मन में स्वाभाविक रूप से सोवियत जनतंत्र के प्रति ठीक इसीलिए सहानुभूति जागृत होती है कि वे उसमें सर्वहारा जनवाद देखते हैं, एक ऐसा जनवाद जो गरीबों के लिए है, न कि ऐसा जनवाद जो धनवानों के लिए हो, जैसा कि हर पूंजीवादी जनवाद, अच्छे से अच्छा पूंजीवादी जनवाद भी, वास्तव में होता है।

पूंजीवादी नौकरशाह, संसद के पूंजीवादी सदस्य, पूंजीवादी न्यायाधीश हमारे ऊपर शासन करते हैं (और हमारे राज्य को "ढालते" हैं)–यह सीधा-सादा, स्पष्ट तथा निर्विवाद सत्य है, जिसे सभी पूंजीवादी देशों में, जिनमें सबसे अधिक जनवादी पूंजीवादी देश भी शामिल हैं, शोषित वर्गों से संबंध रखनेवाले लाखों-करोड़ों लोग अपने जीते-जागते अनुभव से जानते हैं, प्रतिदिन महसूस करते और समझते हैं।

परन्तु रूस में नौकरशाही मशीनरी को बिलकूल चकनाचूर कर दिया गया है, उसकी ईंट से ईंट बजा दी गई है, पुराने न्यायाधीशों को चलता कर दिया गया है, पूंजीवादी संसद को भंग कर दिया गया है और ठीक मजदूरों और किसानों का ही प्रतिनिधित्व कहीं ज्यादा उनकी पहुंच के भीतर कर दिया गया है, उनकी सोवियतों ने नौकरशाहों का स्थान ले लिया है या उनकी सोवियतों ने नौकरशाहों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया है और उनकी सोवियतों को न्यायाधीशों को निर्वाचित करने का अधिकार दे दिया गया है। अकेली यही बात इसके लिए काफी है कि सभी उत्पीड़ित वर्ग यह मान लें कि सोवियत सत्ता, सर्वहारा वर्ग के अधिनायकत्व का वर्तमान रूप, सबसे अधिक जनवादी पूंजीवादी जनतंत्र की तुलना में भी कई लाख गुना अधिक जनवादी है।

काउत्स्की इस सचाई को नहीं समझ पाते, जो हर मजदूर के लिए इतनी साफ और स्पष्ट है, क्योंकि वे यह प्रश्न करना "भूल चुके हैं", "सीखने के बावजूद भूल चुके हैं": जनवाद किस वर्ग के लिए? वे "शुद्ध" (अवर्गीय? या वर्गेतर?) जनवाद के दृष्टिकोण से तर्क करते हैं। वे शाइलाक* की तरह तर्क करते हैं: मेरा "एक पौंड मांस" बस और कुछ नहीं। सभी नागरिकों की समानता–नहीं तो जनवाद है ही नहीं।

हमें विद्वान काउत्स्की से, "मार्क्सवादी" और "समाजवादी" काउत्स्की से पूछना चाहिए:

क्या शोषितों और शोषकों के बीच समानता हो सकती है?

यह एक बेहूदा बात है, यह समझ में नहीं आ सकती कि हमें दूसरे इंटरनेशनल के सैद्धांतिक नेता द्वारा लिखी गयी पुस्तक पर बहस करते समय ऐसा प्रश्न पूछना पड़े। परन्तु "जब ओखली में सर दे दिया, तो मूसल से क्या डर" और काउत्स्की के बारे में लिखने का बीड़ा उठा लिया, तो मुझे इस विद्वान आदमी को यह समझाना ही पड़ेगा कि शोषकों और शोषितों के बीच समानता क्यों नहीं हो सकती। ●

* शेक्सपियर के नाटक 'वेनिश का सौदागर' का पात्र

अंकिता भंडारी हत्या के मामले की न्यायिक जांच हो
–एआईएमएसएस

एआईएमएसएस की महासचिव कॉमरेड छवि मोहंती ने 9 जनवरी को जारी प्रेस बयान में उत्तराखंड के अंकिता हत्या के मामले की निष्पक्ष न्यायिक जांच की मांग की, क्योंकि आरोप है कि इस वीभत्स घटना में एक वीआईपी शामिल है।

उत्तराखंड के संघर्षरत लोगों और मृतका के माता-पिता के साथ एआईएमएसएस ने अपनी एकजुटता जतायी, जो न्याय के लिए संघर्षरत हैं।

हमें याद है कि 2022 में उत्तराखंड के ऋषिकेश में गंगा-भोगपुर के वनतंत्रा रिजॉर्ट में एक रिसेप्शनिस्ट अंकिता का कथित तौर पर बलात्कार किया गया था और बाद में उसकी हत्या कर दी गई थी, क्योंकि उसने एक वीआईपी के साथ सेक्सुअल फेवर करने से मना कर दिया था। लोगों ने विरोध किया और दोषियों को गिरफ्तार कर दोषी ठहराया गया। लेकिन, एक ईआईपी का शामिल होना रहस्य बना रहा। लेकिन अब 3 साल बाद, कुछ खबरों के मुताबिक, इस वीआईपी की पहचान खुलकर सामने आ गई है, जिसे सजा नहीं मिली और लोग अंकिता भंडारी को इंसाफ दिलाने के लिए इस मामले को फिर से खोलने के लिए आन्दोलन कर रहे हैं।

एआईएमएसएस ने लोगों से अपील की कि जब तक दोबारा जांच नहीं हो जाती और जो दोषी बरी हो गया है, अगर वह दोषी पाया जाता है, तो उसे सजा नहीं मिलती, तब तक वे एकजुट रहें।

कॉमरेड भगवान रेड्डी और अन्य नेताओं की गिरफ्तारी की एआईकेकेएमएस ने की कड़ी निंदा
तत्काल बिना शर्त रिहाई की उठायी मांग

ऑल इण्डिया किसान खेत मजदूर संगठन (एआईकेकेएमएस) के अखिल भारतीय सचिवमंडल सदस्य और कर्नाटक राज्य कमेटी के सचिव कॉमरेड भगवान रेड्डी की गिरफ्तारी की संगठन ने कड़ी निंदा की है। एआईकेकेएमएस और संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) के नेता की रिहाई के लिए 2 जनवरी 2026 को देशव्यापी विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया गया।

कॉमरेड भगवान रेड्डी बीजापुर संघर्ष समिति के कार्यकारी समिति और कोर समिति के सदस्य भी हैं और बीजापुर में सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल बनाने की मांग को लेकर चल रहे निरंतर जन आंदोलन के प्रमुख नेताओं में से एक हैं। यह आंदोलन सरकार द्वारा पीपीपी (सार्वजनिक-निजी भागीदारी) मॉडल लागू करने के प्रयास का विरोध कर रहा है।

कई दिनों से शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक आंदोलन जारी है, क्योंकि सरकार बार-बार जनता की जायज मांगों को नजरअंदाज कर रही है। इस आंदोलन को बीजापुर जिले में व्यापक जनसमर्थन मिला।

बीजापुर के प्रभारी मंत्री के आवास के सामने विरोध प्रदर्शन करते हुए कॉमरेड भगवान रेड्डी और अन्य नेताओं को पुलिस ने अवैध रूप से हिरासत में ले लिया, उन पर आईपीसी की धारा 307 जैसी गंभीर गैर-जमानती धाराओं सहित झूठे और मनगढ़ंत मामले दर्ज किये गए और न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

जन स्वास्थ्य सेवाओं की सुलभता की मांग करने वाले जन आंदोलन को दबाने के लिए सरकार द्वारा यह एक घृणित और निरंकुश कार्रवाई है। ये गिरफ्तारियां स्पष्ट रूप से जनता को डराने और संघर्ष को आगे बढ़ने से रोकने के उद्देश्य से की गई हैं।

कॉमरेड भगवान रेड्डी बीजापुर जिले और पूरे कर्नाटक में कई जन आंदोलनों में अग्रणी रहे हैं, लगातार निजीकरण का विरोध करते हुए जन कल्याण के लिए संघर्ष करते रहे हैं। ऐसे नेताओं को निशाना बनाना सरकार के जनविरोधी और कॉरपोरेट-परस्त एजेंडे को उजागर करता है।

एआईकेकेएमएस ने इस दमनात्मक कार्रवाई की कड़ी निंदा की और कॉमरेड भगवान रेड्डी और गिरफ्तार किये गए सभी नेताओं, जिनमें कई महिलाएं भी शामिल हैं, की तत्काल और बिना शर्त रिहाई की मांग की।

किसान नेताओं ने सरकार को चेतावनी दी कि इस तरह के दमन से जनता का संकल्प और मजबूत होगा और बीजापुर में सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की मांग को लेकर संघर्ष और तेज होगा।

PRGI Regn. No. 43022

देश को अंधेरी खाई में न धकेलें – बासद (मार्क्सवादी)

बासद (मार्क्सवादी) पार्टी के संयोजक कॉमरेड मसूद राणा ने 19 दिसम्बर को बांग्लादेश की चिंताजनक स्थिति पर जारी प्रेस बयान में कहा:

"सिंगापुर के एक अस्पताल में इलाज के दौरान, इंकलाब मंच के प्रवक्ता और जुलाई विद्रोह के एक प्रतिभागी उस्मान हादी की एक हत्यारे द्वारा चलायी गई गोली से लगी चोट के कारण मौत हो गई। हम उनके निधन पर गहरा दु:ख व्यक्त करते हैं। एक जुलाई-योद्धा की ऐसी असामयिक मौत हरगिज मंजूर नहीं है। एक बड़े लम्बे फासीवादी शासन के अंत के बाद, देश की पूरी आबादी ने लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम होने की उम्मीद की थी। लेकिन इसके उलट, पिछले डेढ़ साल में कानून-व्यवस्था की स्थिति और भी बदतर होती गई है। नतीजतन, चुनाव अभियान के दौरान उस्मान हादी जैसे एक जुलाई-योद्धा को गोली मार दी गई।

सबसे चिंताजनक बात यह है कि हत्यारों को समुचित तेजी के साथ हिरासत में नहीं लिया जा सका। अंतरिम सरकार अपराधियों को गिरफ्तार न कर पाने की अपनी जिम्मेदारी से किसी भी तरह इनकार नहीं कर सकती। ऐसे संवेदनशील मुद्दे को ठीक से संभालने में विफलता गृह सलाहकार के इस्तीफे की मांग करती है। सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अपराधियों को बिना और देरी के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत नाम दर्ज किया जाए और उन पर मुकदमा चलाया जाए।

जैसे ही उस्मान हादी के निधन की खबर फैली, ढाका सहित पूरे देश में स्वत:स्फूर्त आंदोलन शुरू हो गए। लेकिन चिंता और दुख के साथ जो देखा गया, वह यह कि घोर सांप्रदायिक ताकतों ने पहले तो 'प्रथम आलो' और 'डेली स्टार' अखबार के कार्यालयों में तोड़फोड़ की और फिर आग लगा दी। यहां तक कि एक सांस्कृतिक समूह 'छायानट' के कार्यालय पर भी छापा मारा गया और उसे जला दिया गया। जाने-माने पत्रकार और फासीवाद-विरोधी गैर-समझौतावादी योद्धा नूरुल कबीर पर भी हमला किया गया है।

ऐसी अराजक घटनाएं पूरे देश में देखी जा रही हैं। इसी बीच, मैमनसिंह के भालुका इलाके में अपवित्रता के बहाने एक हिंदू युवक की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। ऐसी क्रूर घटना देश को और अस्थिर और अशांत बनाएगी और सांप्रदायिक विभाजन की आग को भड़कायेगी। ये सभी घटनाएं इस बात की आशंका पैदा कर रही हैं कि आगामी फरवरी में होने वाले चुनाव होंगे या नहीं। लेकिन देश में स्थिरता और कानून-व्यवस्था की स्थिति में सुधार लाने के लिए इस समय चुनाव अनिवार्य हैं। ऐसी अराजकता पैदा करके निहित स्वार्थी तत्व चुनाव रद्द करवाकर अपने नापाक इरादों को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं।

हम सरकार से मांग करते हैं कि वह अराजकता फैलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करे। हम बांग्लादेशवासियों से अपील करते हैं कि वे हादी के हत्यारों पर मुकदमा चलाने के लिए सरकार पर दबाव डालें और प्रतिक्रियावादी ताकतों की उकसावे वाली बातों को खारिज करके शांति व सद्भाव बनाये रखें। हम लोकतंत्र व न्याय कायम करने हेतु अपनी पूरी ताकत से संघर्ष जारी रखेंगे।"

मौजूदा तानाशाही शासन के खिलाफ लड़ रहे ईरानियों को एसयूसीआई (सी) ने दिया पूर्ण समर्थन

एसयूसीआई (सी) के महासचिव कॉमरेड प्रभास घोष ने 13 जनवरी को जारी प्रेस बयान में कहा:

"हम ईरान के तानाशाह शासकों द्वारा ईरान के बहादुर लोगों के खिलाफ किये जा रहे क्रूर अत्याचारों की कड़ी निंदा करते हैं, जो उनके घोर आर्थिक शोषण और राजनीतिक दमन के खिलाफ बहादुरी से लड़ रहे हैं। हम उन बहादुर ईरानियों को अपना पूरा समर्थन देते हैं और उनके प्रति एकजुटता का इजहार करते हैं, जो दमनकारी इस्लामी कट्टरपंथी तानाशाही शासन के खिलाफ वीरतापूर्ण संघर्ष कर रहे हैं। साथ ही हम अमेरिकी साम्राज्यवादियों को भी चेतावनी देते हैं कि वे किसी भी बहाने से ईरान के अंदरूनी मामलों में किसी भी तरह से दखल न दें और ईरान के संघर्षरत लोगों को अपना भविष्य अपनी मर्जी से तय करने दें।

हम दुनिया भर के लोगों से भी पुरजोर अपील करते हैं कि वे ईरान के संघर्षरत लोगों के साथ खड़े हों और अमेरिकी साम्राज्यवादियों को ईरान के अंदरूनी मामलों में किसी भी तरह से दखल देने से रोकें।

हम इस महान ऐतिहासिक आंदोलन में अपने प्राणों की आहुति देने वालों के परिवारों के प्रति भी अपनी संवेदना जताते हैं और लोकतांत्रिक अधिकारों की बहाली और आर्थिक शोषण के सबसे बुरे रूप को खत्म करने के मकसद को बुलंद रखने के लिए उनके कुर्बानी के जज्बे को सलाम करते हैं। ईरान की बहादुर जनता जिन्दाबाद!"

उत्तराखंड में उथल-पुथल, अंकिता भंडारी के हत्यारों को सजा देने की मांग

मुख्यमंत्री आवास पर विरोध प्रदर्शन

देहरादून (उत्तराखंड): उत्तराखंड में लोग फिर से सड़कों पर उतर आये हैं। अंकिता भंडारी के हत्यारों को सजा देने और प्रधानमंत्री के करीबी आरएसएस-भाजपा नेताओं की गिरफ्तारी की मांग को लेकर 4 जनवरी को देहरादून में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के घर के सामने हजारों लोग विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए।

2022 में भाजपा मंत्री विनोद आर्य के रिसॉर्ट में रिसॉर्ट की कर्मचारी 19 साल की अंकिता भंडारी की हत्या कर दी गई थी। हाल ही में हरिद्वार में भाजपा के एक पूर्व मंत्री की पत्नी ने खुलासा किया कि इस हत्या में उत्तराखंड के प्रभारी आरएसएस नेता शामिल थे। जैसे ही यह खबर फैली, लोग फिर से विरोध में सड़कों पर उतर आये। 4 जनवरी को हजारों लोगों ने मुख्यमंत्री भवन पर कूच किया। एसयूसीआई (सी)) समेत कई राजनीतिक पार्टियों और जन संगठनों ने विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया।

18 सितंबर, 2022 को रिसॉर्ट मालिक विनोद आर्य ने अंकिता से कहा कि एक वीआईपी को 'स्पेशल सर्विस' दी जानी चाहिए। जब उसने मना कर दिया, तो मालिक के बेटे ने अपने दो साथियों के साथ मिलकर अंकिता की हत्या कर दी और उसकी लाश गंगा नहर में फेंक दी।

हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर एसयूसीआई (सी) सड़कों पर उतर आयी। छात्र संगठन एआईडीएसओ और महिला संगठन एआईएमएसएस ने जन भागीदारी से 'अंकिता भंडारी को इन्साफ दो कमेटी' बनायी। कमेटी के आंदोलन के दबाव में पुलिस को आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए मजबूर होना पड़ा। मुकदमे में तीनों बदमाशों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई। सत्ताधारी भाजपा सरकार ने इस वीआईपी को बचाने के लिए कमजोर आरोप लगाए। लेकिन हाल ही में हरिद्वार के एक पूर्व भाजपा नेता की पत्नी ने इस वीआईपी की पहचान बतायी और मीडिया को एक ऑडियो मैसेज दिया। पता चला है कि वीआईपी प्रधानमंत्री का बहुत करीबी है। लोग समझ सकते हैं कि इसीलिए भाजपा सरकार हत्यारों को सजा देने में बहुत आनाकानी कर रही है।

इस घटना से यह साफ हो गया है कि प्रधानमंत्री का 'बेटी पढ़ाओ-बेटी बचाओ' का नारा कितना खोखला और जुमला है। एसयूसीआई (सी) के उत्तराखंड राज्य प्रभारी कॉमरेड मुकेश सेमवाल ने कहा कि अंकिता भंडारी के हत्यारों को सजा दिलाने की मांग को लेकर पूरे राज्य में मोमबत्ती जुलूस और विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं।

पंजाब यूनिवर्सिटी में जायज आंदोलन की जीत

पंजाब यूनिवर्सिटी बचाओ मोर्चा के बैनर तले 27 दिनों के लगातार विरोध के बाद आंदोलन के दबाव में पंजाब यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ में सीनेट चुनाव की घोषणा कर दी गई है। एक बार फिर यह साबित हो गया है कि सही रास्ते पर एकजुट और लोकतांत्रिक जन आंदोलनों के जरिये जायज मांगें पूरी करायी जा सकती हैं।

ओडिशा की जननेता कॉमरेड वीणापाणि दास का निधन

ओडिशा की सीनियर जननेता, एसयूसीआई (कम्युनिस्ट) के राज्य सचिवमंडल की सदस्य और एआईएमएसएस की पूर्व राज्य अध्यक्ष कॉमरेड वीणापाणि दास ने लंबी बीमारी के बाद 22 दिसंबर को भुवनेश्वर में आखिरी सांस ली। वे 79 साल की थीं।

पारिवारिक सूत्रों से कॉमरेड वीणापाणि दास स्कूल के दिनों में महान मार्क्सवादी दार्शनिक कॉमरेड शिवदास घोष के संपर्क में आईं। बाद में, राउरकेला में रहते हुए पार्टी की पूर्व केन्द्रीय कमेटी सदस्य और उस समय के राज्य सचिव कॉमरेड तापस दत्ता के साथ उन्होंने शोषित लोगों की मुक्ति के लिए क्रांतिकारी संघर्ष में अपनी पूरी जिंदगी लगाने का फैसला किया। वे ओडिशा में पार्टी की पहली महिला कार्यकर्ता थीं। उस समय के दकियानूसी सामाजिक माहौल में उस राज्य की महिलाओं के लिए क्रांतिकारी आंदोलन में आगे आने में काफी दिक्कतें थीं। उन दिक्कतों को पार करके उन्होंने छोटे से लेकर बड़े तक, हर उम्र के लोगों से बहुत सम्मान पाया। उन्होंने राजनैतिक क्षेत्र में अपने कट्टर विरोधियों से भी इज्जत और प्यार कमाया।

1970 के दशक की शुरुआत में उन्होंने भंडारीपोखानी इलाके और अभी के भद्रक जिले के जाजपुर जिले की इंचार्ज के तौर पर काम किया। 1974 में कटक में एआईडीएसओ के पहले अखिल भारतीय सम्मेलन से पहले उन्होंने कटक में काम करना शुरू कर दिया था। कॉमरेड तापस दत्ता समेत कुछ पूरा-वक्ती कार्यकर्ताओं की रोजमर्रा की जिंदगी पैसे की दिक्कतों की वजह से बहुत मुश्किल थी। उन्होंने पार्टी में काम करते हुए ट्यूशन और दूसरे तरीकों से पार्टी के लिए पैसे जुटाने की कोशिश की। जब ओडिशा में एआईएमएसएस का काम शुरू हुआ, लगभग उसी समय उन्हें संगठन की जिम्मेदारी दी गई। 1977 में, उन्हें संगठन की राज्य अध्यक्ष चुना गया।

पार्टी की राज्य सांगठनिक कमेटी की सदस्य के तौर पर कॉमरेड बीनापानी दास ने 1970 के दशक के आखिर से ही एक अहम रोल निभाया है। 2018 में उन्हें ओडिशा राज्य कमेटी के सचिवमंडल की सदस्य चुना गया।

ओडिशा में वाम-जनवादी आंदोलन में उनकी अहम भूमिका, खासकर जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में चले ऐतिहासिक आंदोलन की वजह से उन्हें उस राज्य के सम्मानित मानवतावादी हस्तियों नवकृष्ण चौधरी और मालती चौधरी का प्यार मिला। उन्होंने एआईएमएसएस और पार्टी संगठन को बढ़ाने के काम के लिए ओडिशा के कई जिलों के दौरे किये।

कॉमरेड वीणापाणि दास का पांच दशक लंबा क्रांतिकारी जीवन-संघर्ष, खासकर उनके परिवार का पूरी तरह से एक पार्टी परिवार बनने का संघर्ष, हमें हमेशा एक सबक के तौर पर प्रेरित करेगा।

कॉमरेड वीणापाणि दास लाल सलाम

दिल्ली में शिक्षा बचाओ कन्वेंशन

30 दिसंबर को, ऑल इंडिया सेव एजुकेशन कमेटी (एआईएसईसी) की दिल्ली इकाई ने 'शिक्षा क्षेत्र में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का असर और जन शिक्षा नीति की भूमिका' विषय पर एक सभा का आयोजन किया।

सभा के मुख्य वक्ता कमेटी के अखिल भारतीय महासचिव प्रोफेसर तरुण कांति नस्कर थे।

इसके अलावा, प्रोफेसर नंदिता नारायण, प्रोफेसर अरुण कुमार, प्रोफेसर दिव्येंदु मैती, प्रोफेसर सचिदानंद सिन्हा और प्रोफेसर मधु प्रसाद ने अपने भाषणों में सरकार की शिक्षा नीति के खतरनाक पहलुओं पर रोशनी डाली।

सभा का संचालन कमेटी की दिल्ली राज्य सचिव शारदा दीक्षित ने किया।

Printed and published by Com. Satyawan on behalf of the Central Committee of the Socialist Unity Centre of India (Communist) and printed at M/s Marutinandan Printers and Publishers, Shakti Complex,6/18, Sameypur Industrial Area, Delhi-110042 and published at 3A/38, WEA, Satnagar, Karol Bagh, New Delhi-110005.
Editor: Comrade Satyawan, Member, Central Committee, SUCI(C). **Phone No. : 9416763089, 9868350503** Email: **sarvaharadrishtikon@gmail.com**